रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/92 REGISTERED NO. DL—33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1992 (फाल्गुन 17, 1913)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1992 (PHALGUNA 17, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 7 मार्च 1992

भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं० एफ(8) 70/बी/52 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण में (31 मार्च, 1991 को समाप्त तिमाही के लिए) निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है जिसके सम्बन्ध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद हैं कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गए सम्बन्धित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, बम्बई को संसूचित करें ।

सूची 'क'

प्रतिभूति का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम में जारी की गई	किस तारीख से ब्याज लागू	डुप्लीकेट जारी करने और/या उन्मोचन मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किए गए आदेश की संख्या और तारीख
1	2	3	4	5	6
		कलकत्ता मंडल—3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946			
सीए०-322828	11,700/-	भारतीय रिजर्व बैंक	15-9-80	मुख्य प्रबन्धक, बैंक आफ इण्डिया चौरिंघी स्केअर शाखा, कलकत्ता ललिता रॉय की ओर से	संयुक्त प्रबन्धक का आदेश दिनांक 8-1-91 डी० वाई० नं० एल० सी० ओ० 159/90-91 दिनांक 9 जनवरी 1991 फाईल सं० I 2445 मामला क्र० 846
सीए० 299491	1,100/-	कमला सेन गुप्ता	15-9-77	—वही—	—वही—

(ह०) अपठनीय
मुख्य लेखाकार
भारतीय रिजर्व बैंक

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 21 फरवरी 1992

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस)

नं० 1-सी० ए० (7)/19/92—चूंकि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स अधिनियम 1949 (सन् 1949 का 38वां) की धारा 30 की उपधारा (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 में संशोधनों का मसविदा 21 सितम्बर, 1991 को भारत के राजपत्र के भाग 3 धारा 4 के पृष्ठ संख्या 2897 से 2908 पर इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की दिनांक 4 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 1-सी०ए० (7)/19/91 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था ।

और चूंकि कथित राजपत्र सर्वसाधारण के लिए 25 सितम्बर, 1991 को उपलब्ध कराया गया था ।

और चूंकि कथित मसविदा पर सर्वसाधारण से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की परिषद् द्वारा विचार किया गया और केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित किए गए हैं ।

अब एतद् द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित परिषद्, केन्द्र सरकार की अनुमति से चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जैसे:—

1. (i) इन विनियमों को चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स (संशोधन) विनियम, 1992 माना जायेगा ।

(ii) यह विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू माने जायेंगे ।

2. चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 में —

(i) निवर्तमान विनियम 23, 24, 25 तथा 26 को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"23(1) एन्ट्रेन्स परीक्षा के लिये प्रवेश शुल्क एवं पाठ्यक्रम :

एन्ट्रेन्स परीक्षा में किसी भी प्रत्याक्षी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक उसने विनियम 2 के उप विनियम (1) के अनुच्छेद (9) के प्रावधानों के तहत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो अथवा स्नातकीय पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहा हो ।

बशर्ते जो प्रत्याशी 1 जनवरी, 1985 के उपरांत सम्पन्न एन्ट्रेन्स परीक्षा में बैठा हो और तीन बार कथित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है उसे एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(2) सभी प्रत्याशियों को एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रवेशार्थ शुल्क का भुगतान करना होगा जो समय-समय पर कौंसिल द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

(3) एन्ट्रेन्स परीक्षा में प्रवेशार्थ प्रत्याशियों की उन विषयों में परीक्षा ली जायेगी जिनका निर्धारण अनुसूची "बी" के पैरा 1 में किया गया है ।

(4) इन विनियमों कि किसी भी उल्लेख के बावजूद कौंसिल को यह अधिकार होगा कि वह फाउंडेशन परीक्षा शुरू होने के उपरांत किसी भी समय एन्ट्रेन्स परीक्षा को समाप्त कर दें ।

24. फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिये पंजीकरण

(1) किसी भी प्रत्याशी को फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए तब तक पंजीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने भारत में विधि सम्मत रूप से गठित किसी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष समझी जाने वाली केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो ।

(2) उपरोक्त उप विनियम (1) में किसी भी उल्लेख के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष समझी जाने वाली सरकार अथवा कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा में बैठा है उसे भी कौंसिल के तत्वावधान में गठित कोचिंग संगठन द्वारा फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए अंतरिम रूप से पंजीकृत कर दिया जायेगा । बशर्ते जिस व्यक्ति को अंतरिम पंजीकरण दिया गया है उसने अंतरिम पंजीकरण से 6 महीनों के अन्दर कोचिंग संगठन को इस आशय के संतोषजनक प्रमाण दे दिए हैं कि उसने कथित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है । जो व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित अवधि तक इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहेगा उसका अंतरिम पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा और जो भी पंजीकरण शुल्क अथवा शिक्षा शुल्क उसने दिया है उसका कोई भी भाग वापस नहीं किया जायेगा तथा इन विनियमों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक निर्देशों को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जायेगी ।

(3) फाउंडेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व प्रत्याशियों को शुल्क का भुगतान करना होगा जो समय-समय पर कौंसिल द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

25. (1) फाउंडेशन परीक्षा के लिये प्रवेश, शुल्क एवं पाठ्यक्रम

किसी भी प्रत्याशी को फाउंडेशन परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह किसी भी नाम से जाने वाले कोचिंग संगठन के प्रधान से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि वह कोचिंग संगठन के पास पंजीकृत हुआ है और उसने डाक शिक्षा योजना के संबंध में सभी आवश्यक निर्देशों का पालन किया है ।

बशर्ते कि वाणिज्यक स्नातक जिसने कि स्नातक परीक्षा एकाउंटेन्सी आडिटिंग, मर्किन्टाइल अथवा कोर्मशियल लाज विषयों में, परीक्षा के पूर्ण अंकों का 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, अथवा वाणिज्य स्नातक के अलावा दूसरे स्नातक जिसने अन्य विषयों के साथ अंक गणित में स्नातक परीक्षा, परीक्षा के पूर्ण अंकों का कम से कम 60 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, अथवा वाणिज्य स्नातक के अलावा दूसरे स्नातक जिसने स्नातक परीक्षा अंक गणित के अलावा किसी अन्य विषयों में, स्नातक परीक्षा के पूर्ण अंकों का कम से कम 55 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, को फाउंडेशन परीक्षा पास करने से छूट दी जायेगी, यदि अन्य रूपों में योग्य पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों को इन विनियमों में निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल्ड/आडिट क्लर्क के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी जायगी ।

व्याख्या:—इस विनियम के उद्देश्य हेतु, वाणिज्य स्नातक का अर्थ, उस स्नातक से होगा जिसने इस क्षेत्र में उपलब्ध अन्य विषयों के अलावा, स्नातक परीक्षा एकाउन्टेंसी, आडिटिंग, मर्केन्टाइल अथवा कोर्मशियल लाज के विषय पूर्ण विषयों के रूप में उत्तीर्ण की हो ।

(2) प्रत्याशी को फाउंडेशन परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा जो समय समय पर कौंसिल द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

(3) प्रत्याशियों को फाउंडेशन परीक्षा के लिए अनुसूची "बी" के पैरा 1ए में निर्धारित विषयों में परीक्षा देनी होगी ।

26. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश

किसी भी उम्मीदवार को इण्टरमीडिएट परीक्षा में तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उसने :—

(i) (अ) प्रवेश परीक्षा पास कर ली हो और विनियम 2 के उप विनियम (1) के अनुच्छेद (9) के अन्तर्गत स्नातक हो, अथवा

(ब) फाउंडेशन परीक्षा पास कर ली हो अथवा इन विनियमों के अधीन कथित परीक्षा को पास करने में छूट प्राप्त हो ।

(ii) उसने आर्टिकल्ड क्लर्क अथवा आडिट क्लर्क के रूप में अथवा आर्टिकल्ड क्लर्क (आंशिक रूप से) अथवा आडिट क्लक (आंशिक रूप से) के रूप में 9 महीने की सेवा परीक्षा शुरू होने वाले महीने के प्रथम दिन से तीन महीने पूर्व पूर्ण कर ली हो, और

(iii) किसी भी नाम, पद से जाने वाले कोचिंग संगठन के प्रधान से इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा कि उसने डाक शिक्षा योजना के संबंध में सभी अपेक्षित आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है :—

बशर्ते कि उक्त प्रमाण पत्र उसके निर्गमन की तिथि जो कोचिंग संगठन द्वारा निर्धारित किया जायेगा, से आंकलिक अवधि के लिए वैध होगा जिसके उपरांत प्रत्याशी को उस संबंध में कोचिंग संस्थान द्वारा लागू की गयी शर्तों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करने के बाद नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

II. विद्यमान विनियम 28 और 29 में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है :

28. इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

(1) 1 जनवरी, 1985 के उपरांत संपन्न इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रत्याशी को अनुसूची "बी" के पैरा 2 में निर्धारित समूह तथा विषयों में परीक्षा देनी होगी।

(2) इन विनियमों में किसी भी उल्लेख के बावजूद, परिषद, फाउंडेशन पाठ्यक्रम के शुरू हो जाने के बाद, किसी भी समय सूची "बी" के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट परीक्षा के आयोजन को समाप्त कर सकती है तथा उम्मीदवारों को सूची "बी" के पैराग्राफ 2ए में निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने का आदेश दे सकती है।

29. अंतिम (फाइनल) परीक्षा में प्रवेश

किसी भी प्रत्याशी को अंतिम (फाइनल) परीक्षा में तभी तक प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक उसने :—

(i) इन विनियमों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1964 के अधीन इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1949 के तहत इंटरमीडिएट अथवा प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो अथवा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1949 के अन्तर्गत प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट मिल गयी हो।

(ii) सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है अथवा परीक्षा शुरू होने वाले महीने में प्रथम दिन से न्यूनतम 3 माह पूर्व व्यावहारिक प्रशिक्षण कम से कम 9 महीनों का और प्राप्त करना है।

स्पष्टीकरण

व्यावहारिक प्रशिक्षण की उक्त 9 महीनों की शेष अवधि को आंकलित करते समय आर्टिकल्ड क्लर्क के मामलों में 138 दिन से अधिक लिए गए अवकाश और आडिट क्लर्क के मामले में 184 दिन से अधिक लिये गये अवकाश को ऐसी अवधि माना जायेगा कि उसने आर्टिकल्ड अथवा आडिट सेवा, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत इस अवधि के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त करना है।

(iii) अंतिम परीक्षा में प्रथम प्रवेश तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बीच कम से कम दो फाइनल परीक्षाओं का समय अन्तराल आवश्यक है बशर्ते कि :—

(i) ऐसे विद्यार्थी के मामले में जो कि अपनी व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि के अंतिम छः महीनों के बीच में अंतिम परीक्षा में प्रवेश करता है, इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने तथा अंतिम परीक्षा में प्रथम प्रवेश के बीच केवल एक अंतिम परीक्षा का समय अन्तराल आवश्यक होगा।

(ii) ऐसे विद्यार्थी के मामले में जो कि अपना व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि के समाप्त होने पर अंतिम परीक्षा में प्रवेश लेता है वहां इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने तथा अंतिम परीक्षा में प्रथम प्रवेश के बीच में कोई भी समय अन्तराल आवश्यक नहीं होगा।

III. वर्तमान विनियम 31 में निम्न अनुसार परिवर्तन किया गया है:

31. अंतिम परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

(1) अंतिम परीक्षा के लिए प्रत्याशियों की अनुसूची "बी" के पैरा 3 में निर्धारित समूह तथा विषयों में परीक्षा ली जायेगी।

(2) इन विनियमों में किसी भी उल्लेख के बावजूद, परीषद फाउंडेशन परीक्षा के शुरू हो जाने के उपरांत, किसी भी समय, सूची "बी" के पैराग्राफ 3 के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में, फाइनल परीक्षा के आयोजन को समाप्त कर सकती है, तथा उम्मीदवारों को सूची "बी" के पैराग्राफ 3ए में निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत फाइनल परीक्षा पास करने का आदेश दे सकती है।

विद्यमान विनियम 36, 37 तथा 38 में निम्न प्रकार से परिवर्तन कर दिया जायेगा :—

36. (1) एन्ट्रेन्स एवं फाउण्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्हताएं :—

साधारणतया उस प्रत्याशी को एन्ट्रेन्स परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त किए हैं और सभी प्रश्नपत्रों को मिलाकर कुल अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

(2) फाउंडेशन परीक्षा में उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण माना जायेगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त किए है और सभी प्रश्नपत्रों को मिलाकर कुल अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

37. इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अर्हताएं

(1) इंटरमीडिएट परीक्षा में साधारणतया उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा जिसने दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वह दोनों समूहों में एक साथ बैठ सकते हैं अथवा एक परीक्षा में एक समूह में और किसी आगामी परीक्षा में शेष समूहों के लिए परीक्षा दे सकते हैं।

(2) दोनों समूहों में एक साथ उस प्रत्याशी को उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा जिसने एक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्राप्त किए है और एक साथ लिए दोनों समूहों के सभी प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं।

(3) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में समूह के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा उस समूह के सभी प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें उस समूह में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा।

(4) जिस प्रत्याशी ने इंटरमीडिएट परीक्षा के दोनों ग्रुपों में किसी एक ग्रुप को, इन विनियमों के सूची "बी" का पैराग्राफ 2ए में निर्धारित पाठ्यक्रम में परीक्षा के शुरू

होने से पहले, पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पास कर लिया हो, यह निम्नलिखित तालिकाओं में निर्धारित प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट की अधिकारी होगा, और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जायेगा, यदि वह एक ही परीक्षा के अन्तर्गत बाकी बचे प्रश्नपत्रों में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक, और सभी शेष प्रश्नपत्रों को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता हो।

बशर्ते जिस प्रत्याशी को पांच प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट प्राप्त होगी उसे कथित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा यदि उसने शेष प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

तालिका ए

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1964 के अंतर्गत अनुसूची "बी" के तहत उत्तीर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्र		चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 के सूची "बी" के पैराग्राफ 2ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी भी इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रत्याशियों को छूट प्राप्त करने के प्रश्न-पत्र	
समूह–1			
प्रश्न-पत्र 1	: एकाउंटिंग	प्रश्न-पत्र 1	: एडवांस एकाउंटिंग (समूह-1)
प्रश्न-पत्र 2	: एकाउंटिंग	प्रश्न-पत्र 1	: एडवांस एकाउंटिंग (समूह-1)
प्रश्न-पत्र 3	: आडिटिंग	प्रश्न-पत्र 2	: आडिटिंग (समूह-1)
समूह–2			
प्रश्नपत्र 4	: कास्ट एकाउन्ट्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स	प्रश्न पत्र 4	: कास्ट एकाऊंटिंग (समूह –2)
प्रश्नपत्र 5	: मर्केन्टाइल लॉ एवं कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र 5	: कोर्पोरेट एवं अन्य लॉ (समूह–1)
प्रश्नपत्र 6	: सामान्य वाणिज्य ज्ञान	कुछ नहीं	

तालिका बी

चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स विनियम 1964 की अनुसूची "बी" के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत उत्तीर्ण इंटरमिडिएट परीक्षा के प्रश्न–पत्र अथवा सी० ए० विनियम, 1988 की अनुसूची 'बी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण इंटरमिडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्र		चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 के सूची "बी" के पैराग्राफ 2ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी इंटरमिडिएट परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा	
समूह–1			
प्रश्नपत्र–1	: एकाउन्टिंग	प्रश्नपत्र–1	: एडवांस्ड एकाउंटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र 2ए	: कम्पनी एकाउन्ट्स	प्रश्नपत्र–5	: आयकर तथा केन्द्रीय बिक्री कर (समूह–2)
2 बी	: ऐलीमेंट्स आफ इनकम टैक्स		
प्रश्नपत्र –3	: कास्ट एकाउन्टिंग	प्रश्नपत्र–4	: कास्ट एकाउंटिंग (समूह–2)
प्रश्नपत्र–4	: आडिटिंग	प्रश्नपत्र 5–2	: आडिटिंग (समूह–1)
समूह –2			
प्रश्नपत्र–5	: मर्केन्टाइल लॉ, कम्पनी लॉ एवं इण्डस्ट्रीयल लॉ	प्रश्नपत्र:3	: कोर्पोरेट एवं अन्य लॉज (समूह–1)
प्रश्नपत्र–6	: बिजनेस मैथेमैटिक्स एवं स्टैटिस्टिक्स		कुछ नहीं
प्रश्नपत्र–7	: आर्गेनाइजेशन एवं मैनेजमेंट एवं अर्थशास्त्र	प्रश्नपत्र–6	: आर्गेनाइजेशन एवं मैनेजमेंट तथा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के फंडामैंट्स (समूह–2)

(5) जिन प्रत्याशियों ने इंटरमीडिएट परीक्षा के एक समूह को उत्तीर्ण कर लिया है किन्तु दोनों समूह उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं उन पर ये विनियम तब तक लागू होते रहेंगे जब तक इन विनियमों के सूची "बी" पैराग्राफ 2ए के अन्तर्गत होने वाली इंटरमिडिएट परीक्षा शुरू नहीं हो जाती ।

38. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी अर्हताएं :

(1) जो प्रत्याशी अन्तिम परीक्षा के दोनों समूहों में उत्तीर्ण हो, उसे साधारणतया उत्तीर्ण घोषित माना जायेगा । भले ही वह दोनों समूहों में एक साथ बैठा हो अथवा एक परीक्षा के एक समूह में तथा शेष समूह में किसी आगामी परीक्षा में बैठा हो ।

(2) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तथा उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें दोनों समूहों में एक साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।

(3) जिस प्रत्याशी ने एक परीक्षा में समूह के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उन्हें उस समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।

(4) जिस प्रत्याशी ने फाइनल परीक्षा के दोनों ग्रुपों में किसी एक ग्रुप को, इन विनियमों के सूची "बी" का पैराग्राफ 3ए में निर्धारित पाठ्यक्रम में परीक्षा के शुरू होने से पहले, पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पास कर लिया हो, वह निम्न-लिखित तालिकाओं में निर्धारित प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट की अधिकारी होगा, और परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा यदि वह, एक ही परीक्षा के अन्तर्गत बाकी बचे प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम 40 प्रतिशत और सभी शेष प्रश्नपत्रों को एक साथ मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता हो ।

बशर्ते कि प्रत्याशी ने सात प्रश्नपत्रों में बैठने से छूट प्राप्त कर ली है उन्हें कथित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा किन्तु उसे शेष प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

तालिका सी

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1964 की अनुसूची "बी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण अन्तिम परीक्षा के प्रश्नपत्र		चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस विनियम, 1988 के सूची "बी" पैराग्राफ 3ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी अन्तिम परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा ।
समूह–1		
प्रश्नपत्र–1	: एडवांस्ड एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र–1 : एडवांस्ड एकाउंटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र–2	: एडवांस्ड एकाउंटिंग एवं मैनेजमेंट एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र–2 : मैनेजमेंट एकाउंटिंग एवं वित्तीय विश्लेषण (समूह–1)
प्रश्नपत्र–3	: कास्टिंग	प्रश्नपत्र–5 : एडवांस्ड कास्ट एकाउंटिंग एवं कास्ट सिस्टम (समूह–2)
प्रश्नपत्र–4	: आडिटिंग	प्रश्नपत्र–3 : एडवांस्ड एवं मैनेजमैंट आडिटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र–5	: टैक्सेशन	प्रश्नपत्र–7 : प्रत्यक्षकर (समूह–2)
समूह–2		
प्रश्नपत्र –7	: कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र–4 : कोर्पोरेट लॉज एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (समूह–1)

तालिका 'डी'

तीन समूह प्रणाली के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1985 से पूर्व चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस विनियम, 1964 की अनुसूची "बीबी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण अन्तिम परीक्षा के प्रश्नपत्र		चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस विनियम, 1988 के सूची "बी" पैराग्राफ 3ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी अन्तिम परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा	
समूह–1			
प्रश्नपत्र–1	: एडवांस एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र–1	: एडवान्स एकाउंटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र–2	: फाइनैंनशियल मैनेजमैंट	प्रश्नपत्र–2	: मैनेजमैंट एकाउंटिंग एवं वित्तीय विश्लेषण (समूह–1)
प्रश्नपत्र–3	: आडिटिंग	प्रश्नपत्र–3	: एडवांस एवं मैनेजमैंट आडिटिंग (समूह–1)
समूह–2			
प्रश्नपत्र–4	: कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र–4	: कार्पोरेट लॉज एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (समूह–1)
प्रश्नपत्र–5	: प्रत्यक्ष कर कानून	प्रश्नपत्र–7	: प्रत्यिक्ष कर (समूह–2)
समूह–3			
प्रश्नपत्र–8	: सिस्टम एनालिसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग	प्रश्नपत्र –6	: सिस्टम एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग एवं क्वान्टिटेटिव टैकनिक (समूह–2)
प्रश्नपत्र–9	: कास्ट रिकार्ड्स एवं कास्ट कन्ट्रोल	प्रश्नपत्र–5	: एडवांस्ट कास्ट एकाउंटिंग एवं कास्ट सिस्टम (समूह-2)

तालिका 'ई'

चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स विनियम, 1964 की अनुसूची "बीबी" के अन्तर्गत उत्तीर्ण अंतिम परीक्षा अथवा इन विनियमों के सूची "बी" पैराग्राफ 3ए में वर्णित पाठ्यक्रम के लागू किए जाने से पूर्व विनियम 1988 (दो समूह प्रणाली के अन्तर्गत) के तहत परीक्षा के प्रश्नपत्र	चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स विनियम, 1988 के सूची "बी" पैराग्राफ 3ए में वर्णित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी अन्तिम परीक्षा में छूट जिसके लिए प्रत्याशी अधिकारी होगा
1	2
समूह-1	
प्रश्नपत्र–1 : एडवांस एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र–1 : एडवांस्ड एकाउंटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र–2 : मैनेजमैंट एकाउंटिंग	प्रश्नपत्र–2 : मैनेजमैंट एकाउंटिंग एवं वित्तीय विश्लेषण (समूह–1)
प्रश्नपत्र–3 : आडिटिंग	प्रश्नपत्र–3 : एडवांस एवं मैनेजमैंट आडिटिंग (समूह–1)
प्रश्नपत्र–4 : कम्पनी लॉ	प्रश्नपत्र–4 : कोर्पोरेट लॉज एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (समूह–1)

1	2
समूह–2	
प्रश्नपत्र–5 : प्रत्यक्ष कर नियम	प्रश्नपत्र–7 : प्रत्यक्ष कर (समूह–2)
प्रश्नपत्र–6 : मैनेजमेंट इंफोरमैशन एवं कन्ट्रोल सिस्टम (कोम्बीनेशन "सी")	प्रश्नपत्र–6 : सिस्टम एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग एवं क्वान्टिटेटिव टैक्नीक (समूह–2)
प्रश्नपत्र–7 : सिस्टम एनालिसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग (कम्बीनेशन "बी")	
प्रश्नपत्र –8 : सैक्रेटरियल प्रैक्टिस (कम्बीनेशन "ए")	प्रश्नपत्र–4 : कार्पोरेट लॉज एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस (समूह–1)
प्रश्नपत्र –8 : कास्ट सिस्टम्स एवं कास्ट कन्ट्रोल (कम्बीनेशन "बी")	प्रश्नपत्र–5 : एडवांस कास्ट एकाउंटिंग एवं कास्ट सिस्टम (समूह –2)
प्रश्नपत्र–8 : मैनेजमेंट एवं ओपरेशन आडिट (कम्बीनेशन "सी")	प्रश्नपत्र–3 : एडवांस एवं मैनेजमेंट आडिटिंग (समूह –1)

(5) जिस प्रत्याशी ने चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा के किसी एक समूह में सफलता प्राप्त की है, किन्तु दोनों समूहों में नहीं कर सके हैं उन प्रत्याशियों पर इन विनियमों के सूची "बी" पैराग्राफ 3ए के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाली अन्तिम परीक्षा के शुरू होने तक उन विनियमों के प्रावधानों को ही लागू माने जाएंगे ।

V. विनियम 43 में––

(i) उप–विनियम (6) को हटा दिया जाएगा ,

(ii) वर्तमान उप विनियम (8) के प्रावधानों के स्पष्टीकरण को निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है:––

स्पष्टीकरण

इस विनियम का उद्देश्य है कि जब कोई सदस्य विनियम 51 तथा 72 के तहत स्वीकृत वित्तीय, वाणिज्यक अथवा औद्योगिक संस्थानों में एक अथवा अधिक में सेवा करने के उपरांत प्रैक्टिस को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में सहित अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है वह तीन वर्षों से सतत प्रैक्टिस कर रहा है––ऐसा माना जाएगा ।

निवर्तमान विनियम 45 के उप–विनियम (1) की क्लाज (बी) को निम्नलिखत से बदल दिया गया है :––

"(बी) इस प्रकार का प्रत्याशी––

(i) आर्टिकल्स के शुरू होने के दिन 18 वर्ष से कम का न हो ।

(ii) इन विनियमों के तहत या तो उसने फाउन्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या फाउन्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने से उसको छूट प्राप्त हो गई हो––

बशर्ते कि जिन स्नातक प्रत्याशियों ने एन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें स्वयं को आर्टिकल्ड क्लर्कस के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए ग्राह्य माना जाएगा ।"

विनियम 46 के वर्तमान उप विनियम (5) को हटा दिया गया है । विनियम 51 के वर्तमान उप विनियम (2) में निम्न अनुसार संशोधन किया गया है :––

"(2) व्यावहारित प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि अन्तिम वर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि 9 महीनों से 12 महीनों तक मानी जाएगी ।"

विनियम 57 में––

(i) निवर्तमान उप विनियम (3) को हटा दिया गया है ।

(ii) उप–विनियम (4), शब्द, कोष्ठक एवं अंक "उप–विनियम (3)" तथा "उप–विनियम (1) अथवा उप– विनियम (2) के अन्तर्गत आने वाले मामले "में" को हटा दिया गया है ।

वर्तमान उप विनियम 60 को निम्न अनुसार परिवर्तित किया गया है :––

"60. आर्टिकल्ड क्लर्क के लिए कार्यकारी घंटे :

कौंसिल द्वारा निर्गमित निर्देशों के अनुसार आर्टिकल्ड क्लर्क के कार्यकारी घंटे प्रति सप्ताह 35 घंटे होंगे जो समय-समय पर प्रिंसीपल द्वारा नियमित किए जाएंगे ।"

XI. निवर्तमान उप विनियम 64 में निम्न अनुसार संशोधन किया गया है ।"

"64. कौंसिल को प्रतिवेदन :

(1) प्रिंसिपल आर्टिकल्ड क्लर्क द्वारा लिए गए प्रशिक्षण का पूरा हिसाब किताब और उसकी प्रगति का रिकार्ड इस प्रकार रखेगा जो कौंसिल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

(2) जब भी कौंसिल द्वारा अपेक्षित समझा जाएगा प्रशिक्षण का पूरा रिकार्ड प्रिंसीपल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । प्रिंसीपल के निधन हो जाने पर उसके कानूनी प्रतिनिधि अथवा जीवित पार्टनर उस रिकार्ड को कौंसिल के पास प्रस्तुत करेंगे, जैसे भी और जब भी कौंसिल चाहेगी ।"

XII. विनियम 68 के वर्तमान उप विनियम (5) में निम्न अनुसार संशोधन किया गया है :—

"(5) आडिट क्लर्क के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार किसी भी सदस्य को होगा किन्तु उस व्यक्ति को निम्नलिखित दरें जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आडिट क्लर्क का स्थान कहां है, पर वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पास अथवा प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को संस्था, जिसमें वह पार्टनर है, में नियुक्त करने का अधिकार होगा :—

(ए) 10 लाख अथवा अधिक की आबादी वाले शहरों में रु० 750/– प्रति माह

(बी) दस लाख से कम आबादी वाले शहरों/कस्बों में रु० 500/– प्रति माह

स्पष्टीकरण

इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए आबादी के आंकड़ों का आंकलन अन्तिम प्रकाशित भारत की जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर किया जाएगा ।"

XIII. विनियम 69 में, उप–विनियम (1) की क्लाज (बी) को निम्न अनुसार संशोधन किया गया है :—

"(बी) ऐसा कोई भी व्यक्ति :

(1) आडिट सेवा शुरू करने के दिन 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है ।

(2) फाउन्डेशन परीक्षा या तो उत्तीर्ण कर चुका है या इन विनियमों के तहत फाउन्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त कर सका हो ।

बशर्ते जिन स्नातकों ने ऐन्ट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें आडिट क्लर्क के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराए जाने के लिए ग्राह्य माना जाएगा ।"

XIV. विनियम 69 के वर्तमान उप–विनियम (5) को हटा दिया जाएगा,

XV. विनियम 72 के निवर्तमान उप–विनियम (2) में निम्न प्रकार मेर्त संशोधन किया गया है :—

"(2) औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि व्यवहारिक प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि के अन्तिम वर्ष के मध्य 9 माह से 12 माह के मध्य होगा ।"

XVI. अनुसूची "ए" में वर्तमान फार्म "10" के उपरांत निम्नलिखित फार्म को जोड़ दें :—

"फार्म 10ए

(देखें विनियम 40)

अनुक्रमांक———————

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

(प्रतिरूप)

फाउन्डेशन परीक्षा प्रमाणपत्र

यह अभिप्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————निवासी———————ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा आयोजित फाउन्डेशन परीक्षा माह———————सन् 19———— में उत्तीर्ण कर ली है ।

आज दिनांक———————सन् 19————को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की सामान्य मुहर के अन्तर्गत प्रदत्त

सील सचिव"

XVII. अनुसूची "बी" में—

(i) पैरा 1 के अन्त में निम्नलिखित नया पैरा जोड़ें, जैसे :—

(i) फाउन्डेशन परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र एवं पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र 1—लेखांकन के मौलिक तत्व

(एक प्रश्नपत्र–तीन घंटे–100 अंक)

ज्ञान का स्तर—बुनियादी ज्ञान

उद्देश्य : सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कराने का विश्वास दिलाना जो व्यावसायिक परीक्षा की नींव मजबूत करने के उद्देश्य से पर्याप्त है ।

विस्तृत विषय वस्तु :

1. मापन विषय, आय विषय के रूप में एकाउंटिंग तथा सम्बद्ध एकाउंटिंग विचार । अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी से एकाउंटिंग का सम्बन्ध । समाज में एकाउन्टैंट की भूमिका ।

2. गलतियों के शुद्धिकरण सहित कच्चा चिट्ठा (ट्रायल बैलेंस) तैयार करने तथा अन्तिम एकाउन्ट्स (गैर–निगमित तत्व के लिए) तैयार करने के संबंध में एकाउंटिंग प्रक्रिया

3. मूल्य ह्रास एकाउंटिंग तथा उसकी पद्धतियां

4. इन्वेन्टरी वैल्यूशन

5. विशेष व्यवसाय कार्रवाई के लिए एकाउंटिंग

(ए) प्रेषण

(बी) संयुक्त जोखिम

(सी) औसतन नियम विधि, तथा

(डी) बिल्स आफ एक्सचेंज एवं प्रामिसरी नोट्स

6. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स

7. भागीदारी एकाउन्टस में साधारण समस्याएं

8. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र जिसमें व्यावसायिक संस्थानों के लेखा भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न पत्र–2–मर्केन्टाइल लॉ

(एक प्रश्नपत्र–समय 3 घंटे––100 अंक)

ज्ञान का स्तर : बुनियादी स्तर

उद्देश्य : विद्यार्थी को कानून संबंधी प्रावधानों की उन शाखाओं का ज्ञान हासिल कर लिया है जिसके लिए वे अपने व्यावसायिक कार्यों के सामान्यतः लगे रहते हैं––इस बात का विश्वास दिलाना होगा।

विस्तृत विषय वस्तु :

1. भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 जिसमें इन्डेमिनिटी तथा गारंटी, बैलमेंट एवं प्लेज एवं एजेंसी शामिल हैं।

2. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

3. वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930

प्रश्न पत्र–3 गणित एवं सांख्यकी

(एक प्रश्नपत्र––समय– 3 घंटे––100 अंक)

ज्ञान का स्तार : बुनियादी ज्ञान

उद्देश्य : इस बात का विश्वास दिलाना कि विद्यार्थी में इस आशय का बुनियादी समझ है कि उसने व्यवसाय समस्याओं के संबंध में उनके प्रारम्भिक क्रियान्वयन तथा महत्वपूर्ण परिमाणात्मक उपकरण के बारे में जानकारी हासिल कर ली है।

विस्तृत विषय वस्तु :

(अनुभाग ए––गणित–अंक 50)

1. अंक आधार एवं दोहरा अंक गणित, प्रदत्त आधार का परिवर्तन, दोहरी भिन्न।

2. डालनियर, क्वेडरेटिक, एक्सपोनेंटियल एवं लागरिथमिक फंक्सन। ब्रेक-ईवन प्वांइट्स का विचार एवं निर्धारण

3. सीरीज सहित अंक गणित एवं रेखागणित अनुक्रम

4. क्रम परिवर्तन एवं जोड़

5. मैट्रीसेस–अर्थ और संचालन, मैट्रीक्स इन्वर्जन, मैट्रीक्स इन्वर्जन द्वारा तथा पाइवोटल रिएक्शन पद्धति द्वारा भी लाइनियर समीकरण की प्रणाली का समाधान।

6. दी परिवर्तनशील लाइनियर विषमताओं के ग्राफ

7. कैलकुलस

(ए) ट्रिगनोमैटरी का प्रारंभिक ज्ञान :––विद्यार्थी को इंटगरल कैलकुलस सीखने के लिए प्रोत्साहन देना जो उद्धृत एंगिल, अतिरिक्त फार्मूले, मल्टीपल एवं सब मल्टीपल एंगिल्स, ट्रांसफोरमेशन आफ सम्स इंटू प्रोडक्शन एवं विलोमतः इन्वर्स सर्कुलर की परिभाषा से संबंद्ध ट्रिगनोमैट्रिक रेशो की सहायता से किए गए हों।

(बी) एलीमेंटस आफ डिफ्रेनशिशएशन, सिंपल एप्लीकेशन आफ डिफ्रेन्शियल को–एफिशिएन्टस, मेक्सीमा एवं मिनीमा आफ यूनीवेरिएट फंक्शन्स, रूल्स, आफ अन्टीग्रेशन फार इनडेफिनिट एंड डेफीनिट इंटीगरल्स। एकाउंटिंग एवं बिजनेस समस्याओं के संबंध में सिम्पल एप्लीकेशन आफ इंटीग्रेशन।

(अनुभाग बी––सांख्यिकी––अंक 50)

1. आंकड़ों का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्ध

2. सेंट्रेल टेंडेंसी एवं डिस्पर्जन के मानदंड

3. कोरिलेशन एवं रिग्रेशन (लाइनियर एवं बाईवेरियेट केवल)

4. प्रोबेबिलीटी एवं एक्सेपेक्टेड वैल्यू

5. सैद्धान्तिक वितरण के तत्व––बाईनोमियल फाईससन नार्मल

6. मानक त्रुटियों का विचार, इंटरवल एस्टीमेशन डिटरमिनेशन आफ सैम्पस साइन, अस्ट्स आफ हाईपोथिसिस, एनालिसिस आफ वेरिएंस

7. टाइम सीरीज एवं फोर कास्टिंग

8. इंडेक्स नम्बर्स

9. स्टेटिस्टिकल्स डिसीजन थ्योरी, पे–आफ एण्ड रिग्रेट मैट्रीसेस

सम्भाषना के बिना निर्णय लेना तथा संभावना सहित निर्णय लेना।

प्रश्न पत्र 4––अर्थशास्त्र

(एक प्रश्नपत्र–समय 3 घंटे––अंक–100)

ज्ञान का स्तर : बुनियादी

उद्देश्य : (1) एकाउन्टेंटस के लिए उपयोगी सीमा तक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के गठन का बुनियादी ज्ञान, तथा

(2) इस बात का विश्वास दिलाना कि विद्यार्थी देश के आर्थिक विकास से सुपरिचित है जो उस समय की सरकार जिसमें अर्थव्यवस्था लागू की गयी है, से संबंधित है।

विस्तृत विषय वस्तु :

माइक्रो अर्थशास्त्र

1. अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं उसका क्षेत्र, अर्थशास्त्र मॉडेल्स एवं उनके प्रयोग।

2. मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति के नियम, मांग और पूर्ति की मूल्य सापेक्षता, मांग और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तथ्य, मांग की भविष्यवाणी।

3. उत्पादन का अर्थ, उत्पादन के तत्व, उत्पादन के मापक्रम, लॉ आफ रिटर्न मेजर कम्पोनेंट्स आफ कास्ट्स।

4. बाजार के अर्थ, बाजार के प्रकार, मूल्य के सिद्धान्त एवं विभिन्न बाजार प्रारूप एवं विभिन्न अर्थशास्त्र पद्धति में उत्पादन निर्धारित।

भारतीय माइक्रो अर्थशास्त्र पर्यावरण

1. भारत में आर्थिक विकास—जनसंख्या एवं आर्थिक विकास।

2. भारत में कृषि एवं उद्योग की सामान्य रूपरेखा, भारत में आर्थिक प्रगति के लिए उद्योग एवं कृषि के अन्योन्याश्रित संबंध।

3. सरकार की औद्योगिक नीति, भारत में औद्योगिक विकास—समस्याएं एवं संभावनाएं।

4. भारत में राष्ट्रीय आय—सिद्धान्त एवं क्रियान्वयन

5. भारत में वित्तीय नीति

6. भारतीय आर्थिक सिद्धान्त—वाणिज्यिक बैंकों एवं भारतीय रिजर्व बैंकों के क्रियाकलाप।

7. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार—निर्यात एवं आयात, व्यापार के शेष एवं भुगतान।

(ii) पैरा 2 के अंत में निम्नलिखित नया पैरा जोड़ें; जैसे :—

"(2ए)" : इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र एवं पाठ्यक्रम

समूह—1

प्रश्नपत्र 1—एडवांस्ड एकाउंटिंग

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घंटे—अंक 100)

ज्ञान का स्तर : कार्यकारी ज्ञान

उद्देश्य : विद्यार्थी की इस आशय की योग्यता की परीक्षा लेना कि वह प्रचलित कानूनी अपेक्षाओं एवं व्यावसायिक मानकों के अनुसार व्यावसायिक तथा अन्य संस्थानों के वित्तीय मामलों एवं आर्थिक सौदों को प्रभावित करने वाले एकाउंटिंग रिकार्ड्स एवं अंतिम एकाउन्टस तैयार कर सकने के योग्य है।

विस्तृत विषय वस्तु :

1. विभागीय एकाउन्ट्स एवं शाखा एकाउन्ट्स (विदेशी शाखाओं सहित) रायल्टी, किराया-खरीद एवं किस्त आधार पर बिक्री सौदे, इन्वैस्टमेंट एकाउन्ट्स पैकेजेज एवं एम्पटीज, गुड्स ओन सेल अथवा रिटर्न बायेज एकाउन्ट्स, कान्ट्रेक्ट एकाउन्ट्स, स्टाक की क्षति के लिए बीमा दावों का आंकलन।

2. कृषि फर्मों के एकाउन्ट्स।

3. भागीदारी एकाउन्ट्स की उच्चस्तरीय समस्यायें।

4. कम्पनी एकाउन्ट्स, शेयर्स एवं डिबैंचर्स का निर्गमन एवं शेयर्स तथा डिबैंचर्स की पुनः प्राप्ति, कम्पनी के अंतिम एकाउन्ट्स तैयार करना।

5. बैंकिंग, बीमा एवं निजी कम्पनियों के अंतिम एकाउन्ट्स तैयार करना।

6. विलयन, समावेशन एवं पुनर्गठन संबंधी साधारण समस्याएं।

7. स्टेटमेंट आफ अफेयर्स (जिसमें डिफीशेंसी/सरप्लस एकाउन्ट्स सम्मिलित हैं) तथा कम्पनी बंद करने संबंधी परिसमापन के स्टेटमेंट आफ एकाउन्ट्स।

8. अपूर्ण रिकार्डों से एकाउन्ट्स तैयार करना (सिंगल एंट्री)

9. साधारण रेशो एनालिसिस

10. सरकारी एकाउन्टिंग पद्धति की प्रस्तावना।

प्रश्न पत्र—2 आडिटिंग

(एक प्रश्नपत्र—समय 3 घंटे—अंक 100)

ज्ञान का स्तर : कार्यकारी ज्ञान

उद्देश्य : आडिटिंग की तकनीक, एवं प्रक्रिया तथा सामान्य व्यवसाय परिस्थितियों में उनके क्रियान्वयन की योग्यता के संबंध में विद्यार्थी की समझ का परीक्षण करना।

विस्तृत विषय वस्तु :

1. आडिटिंग :—प्रकृति और क्षेत्र, आडिट प्रक्रिया, आडिट के उद्देश्य, आडिट से संबंधित मूल सिद्धान्त, आडिट के प्रकार, अन्य विषयों के साथ आडिट का संबंध, इंटरन आडिट तथा एक्सटरनल आडिट।

2. आडिट का संचालन :—आडिट कार्यक्रम, वर्किंग पेपर्स, आडिट नोट बुक्स, आडिट फाइल्स—स्थायी आडिट फाइल्स।

3. आडिट एवीडेंस, फिजिकल वेरीफिकेशन, डॉकूमेंटेशन, स्कैनिंग, डायरेक्ट कनफर्मेशन, सिकम्प्यूटेशन, प्रमाणपत्र प्राप्त करना।

4. आंतरिक नियंत्रण पद्धति का आंकलन —विस्तृत चैकिंग की आवश्यकता और उसका प्रभाग।

5. परख चैकिंग—परख (टैस्ट) चैकिंग की पद्धतियां—टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के घटक।

6. भुगतान का आडिट —सामान्य विचार पारिश्रमिक पूंजीगत व्यय अन्य भुगतान एवं खर्चे—छोटे मोटे नगर भुगतान, बैंक में और बाहर भुगतानों का आडिट रोकड खाते के साथ बैंक विवरण का मिलान ।

7. रसीदों का आडिट—सामान्य विचार-नगर बिक्री-ऋणों से प्राप्ति अन्य प्राप्तियां ।

8. खरीदों का आडिट :—नगद और उधार खरीदों की वाउचिंग—फार्वर्ड खरीद—परचेज रिटर्नस ।

9. बिक्रियों का आडिट—नकद व उधार बिक्री माल प्रेषण— स्वीकृति आधार पर बिक्री किराया खरीद अनुबंध के तहत बिक्री-लौटाए जाने वाले पात्र (कन्टेनर)—उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न छूटें—सेल्स रिटर्नस-सेल्स लेजर ।

10. आडिट आफ सप्लायर्स लेजर एवं डैटर्स लेजर—सैल्फ बैलेंसिंग एवं सेक्शनल बैलेंसिंग प्रणाली—कुल अथवा नियंत्रित एकाउन्ट्स लूज लीफ एवं कार्ड लेजर्स-उधार उपभोक्ताओं तथा आपूर्तिकर्त्ताओं से कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट न चुकता किए जाने वाले संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान ।

11. आडिट आफ इमपर्सेल लेजर-पूंजीगत व्यय, बट्टे खाते वाले आय व्यय एवं आय व्यय-बकाया खर्चे एवं आय-मरम्मत एवं नवीनीकरण-रिजर्वस तथा प्राविजन्स के मध्य अंतर एकाउंटिंग के आधार में परिवर्तन स्वरूप अर्थापित्ति ।

12. पूंजी का मूल्यांकन एवं जांच—सामान्य सिद्धान्त अचल पूंजी रद्द पूंजी वर्तमान पूंजी, जिसमें कैश-इन-हैन्ड तथा बैंक में दोनों सम्मिलित—है । इन्वेस्टमेंटस इन्वेन्ट्रीज-फ्रीहोल्ड तथा लीज की सम्पत्ति, ग्रहण प्राप्त होने वाले बिल्स, विधि, ऋण, संयंत्र तथा मशीनरी, पेटेन्ट्स

13. देयताओं की जांच

14. अपूर्ण रिकार्डों की आडिट

15. विभिन्न प्रकार के संस्थानों अर्थात शैक्षित संस्थानों, होटल्स, क्लबों अस्पतालों, किराया खरीद तथा लीजिंग, कम्पनियां इत्यादि (जिसमें बैंक, बिजली कम्पनियां, सहकारी समितियां तथा बीमा कम्पनियां सम्मिलित नहीं है के आडिट के संबंध में विशेष बिन्दु ।

16. लिमिटेड कम्पनियों का आडिट :—आडिटर्स की नियुक्ति, आडिटर्स को हटाना, आडिटर्स के अधिकार तथा कर्तव्य, आडिटर्स प्रतिवेदन, शेयर पूंजी का आडिट, शेयरों का हस्तांतरण ।

17. सरकारी आडिट की विशेषताएं—कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल और उसकी वधानिक भूमिका—सरकार आडिटिंग के मूल सिद्धान्त ।

18. ई० डी० पी० वातावरण में आडिटिंग—मूल विचार ।

प्रश्न पत्र-3 निगमित तथा अन्य अधिनियम

(एक प्रश्नपत्र—समय तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : कतिपय निगमित एवं अन्य नियमों के उपबन्धों के साधारण बोध की जांच तथा उनका व्यावहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग ।

विस्तृत विषय वस्तु :

1. दि कम्पनी एक्ट, 1956 धारा 1 से 145

2. दि नेगोशिएबल एन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881

3. दि पेमेंट आफ बोनस एक्ट 1963

निम्नलिखित अधिनियमों का मूलभूत ज्ञान

4. दि पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972

5. दि एम्पलाईज प्राविडेंट फण्ड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952

6. दि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860

7. दि को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912

ग्रुप-II

प्रश्न पत्र 4—लागत लेखा विधि (कोस्ट एकाउंटिंग)

(एक प्रश्नपत्र—3 घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : लागत आंकलन संकल्पनाओं की समझ कर निर्धारण तथा लागत आंकलन की विधियों तथा प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग

विस्तृत विषय वस्तु :

1. लागत आंकलन का उद्देश्य, महत्व तथा लाभ, लागत संकल्पनाओं लागत आंकलन के प्रकार, लागत आंकलन पद्धति का प्रतिष्ठापन, एक अच्छी लागत आंकलन पद्धति की अनिवार्यताएं, लागत आंकलन तिथि तथा आर्थिक लेखा तिथि का स्तर, लागत आंकलन के मूल तत्व, लागत एकक एवं लागत केन्द्र

2. सामग्री :

(क) सामग्री क्रय करने की पद्धति, उसकी प्राप्ति तथा निरीक्षण ।

(ख) सामग्री का नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य, सामग्री का वर्गीकरण तथा संहिताकरण, मालद्वीप नियंत्रण पद्धति, भंडार स्तर का नियतन, भंडार की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा, पुनरआदेश का परिमाण, पुनराआदेश की सीमा, ए० बी० सी०, दि कोष्ठ पद्धति, सतत मालसूची प्रणाली मालद्वीप का प्रत्यक्ष सत्यापन ।

(ग) सामग्री निर्गमन कार्यविधि सामग्री का बीजक, सामग्री की वापसी सामग्री का स्थानांतरण ।

(घ) भंडार के अभिलेख, कोष्ठ पत्र के भंडार खाता बही, विक्रेता तथा भंडार ग्रह को सामग्री की वापसी, सहित निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन ।

(च) छीजन, रद्दी सामग्री, जीर्ण सामग्री, दोषपूर्ण तथा अप्रचलित सामग्री का लेखाकरण ।

(छ) उपकरणों, नमूनों, रूपांकनों, नीले नक्शों, ठप्पों तथा अल्प अवधि मूल्य की अन्य ऐसी ही परिसंपत्ति के नियंत्रण का लेखाकरण ।

3. श्रम

(क) श्रम लागत नियंत्रण तथा उसका महत्व, समय लेखा पद्धति, समय अंकण तथा उसके उद्देश्य, समय लेखन की पद्धतियां, समय गति अध्ययन ।

निष्कार्य समय तथा अतिरिक्त समय पर नियंत्रण तथा लागत लेखन में उसका निरुपण—श्रमिक आवर्त उसका कारण तथा मापन प्रणाली श्रमिक आवर्त का प्रभाव—श्रमिक आवर्त को न्यूनतम रखने के उपाय श्रमिक आवर्त की लागत तथा श्रमिक आवर्त की लागत का लेखन में निरुपण ।

(ख) बोनस तथा प्रेरणामूलक योजनाओं सहित मजदूरी के भुगतान की प्रणालियां, कार्य मूल्यांकन गण क्रमांकण कार्य मूल्यांकन की प्रणालियां ।

4. उपरिव्यय

(क) विनिर्माण उपरिव्यय का लेखाकरण तथा नियंत्रण, विनिर्माण उपरिव्यय का समूहीकरण तथा संहिताकरण, संग्रेह एवं विभागीकरण तथा पुनप्रभाजन, उपरिव्यय अंतर्लयन प्रणाली उपरिव्यय के अधिक तथा न्यून अंतर्लयन का निरुपण ।

(ख) प्रशासनिक विक्रय तथा वितरण संबंधी उपरिव्यय का लेखाकरण नियंत्रण ।

(ग) लागत लेखों में कुछ विशेष मदों जैसे मूल्ह्रास, पूंजी पर ब्याज, अनुसंधान तथा विकास व्यय, पैक्कारी व्यय तथा अनुषंगी हितलाभ आदि का निरुपण ।

5. लागत निर्धारण की प्रणालियां जैसे

(1) कार्य लागत निर्धारण
(2) अनुबंध लागत निर्धारण
(3) खेप लागत निर्धारण
(4) प्रक्रिया लागत निर्धारण—संयुक्त उत्पाद तथा उपोत्पाद
(5) एकांश लागत निर्धारण
(6) प्रचालन लागत निर्धारण तथा सांख्यिकीय लागत निर्धारण

6. (क) लागत आधार सामग्री तथा सूचनाओं की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण विशेषतया लागत आधार सामग्री को तालिकाबद्ध करना, लागत पत्रक तथा लागत विवरण लागत निर्धारण अभिलेख तथा नियमों का सामान्य परिचय (उद्योगानुसार ब्यौरा प्रत्याशित (नहीं) ।

(ख) लागत नियंत्रण लेखे, असमेकित लेखे, लागत तथा आर्थिक लेखों का समाधान लागत तथा आर्थिक लेखों की समेकित प्रणाली ।

7. सीमांत लागत आकलन, अर्ध परिवर्तनीय लागत का नियम, लागत तथा परिवर्तनीय लागत भागों में प्रथक्करण की प्रणालियां, संतुलन स्तर विश्लेषण की संकल्पना, मानक लागत आंकलन तथा प्रसरण विश्लेषण (प्रारंभिक समस्याएं) बजट नियंत्रण (प्रारम्भिक समस्याएं)

8. एक रूप लागत आंकलन तथा अंतः व्यवसाय प्रतिष्ठान तुलना

प्रश्न पत्र 5—आयकर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर

(इंकम टैक्स तथा सैन्ट्रल टैक्स)

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : (क) विद्यार्थियों की आयकर नियम के मुख्यभागीय उपबन्धों के अंतर्निहित मूल सिद्धान्तों की जानकारी की जांच तथा आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत व्यक्ति की आय के अभिकलन में साधारण समस्याओं को हल करने में उनका अनुप्रयोग ।

(ख) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने केन्द्रीय बिक्री कर नियम के मूल सिद्धान्तों का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

परिच्छेद क—आयकर (75 अंक)

विस्तृत विषय वस्तु

आयकर अधिनियम 1961 में दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे कृषि, आय, कर निर्धारित, कर निर्धारण वर्ष, पूंजीगत परिसम्पत्ति, कम्पनी, भारतीय कम्पनी जिसमें जनता की मुख्य रूप से अभिरुचि है, धर्मार्थ उद्देश्य, भारतीय आय व्यक्ति, अल्पावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति, हस्तांतरण ।

—पिछले वर्ष की संकल्पना

– प्रभार का आधार, आवासी हैसियत तथा पूर्ण आय का विषय क्षेत्र
– भारत में प्राप्त की गई मानी हुई/अर्जित हुई मानी गई आय
– आय जो कुल आय का भाग नहीं होती
– आय की मद तथा विभिन्न मदों में आय के अभिकलन से संबंधित अनुबंध

– अन्य व्यक्तियों की कुल आय का निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित करना ।

– आय का समूहन तथा हानि का समंजन या हानि का अगले लाभ से घाटा पूर्ति

– सकल आय में से कटौतियां

– आय कर प्राधिकारी, नियुक्तियां, नियंत्रण, अधिकार क्षेत्र तथा शक्ति

– निर्धारण की कार्यविधि, अपील तथा पुनरीक्षण, विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे उपरोक्त क्षेत्रों में कर निर्धारिती से संबंधित साधारण समस्याओं को हल करेंगे ।

खण्ड ख—केन्द्रीय बिक्री कर (25 अंक)

केन्द्रीय बिक्री कर नियम–1956

प्रश्न पत्र 6—संगठन एवं प्रबन्ध एवं इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के मूल तत्व

(एक प्रश्नपत्र–3 घंटे–100 अंक)

भाग–ए, संगठन एवं प्रबंध (50 अंक)

ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों ने व्यावसायिक लेखापालों से संबंधित संगठन एवं प्रबंध के विभिन्न संकल्पनाओं तथा प्रकार्यों को हृदयंगम् कर लिया है ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. भूमिका

संगठन एवं प्रबंध की मूल संकल्पनाएं संगठन का स्वरूप एवं प्रकार—संगठन के मूल तत्व तथा अर्थव्यवस्था एवं समाज में उनकी भूमिका, प्रबंध–एतिहासिक विकास-प्रबंध के सिद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य–प्रबंध के तत्व, प्रक्रिया एवं प्रकार्य–संगठन एवं प्रबंध पर वातावरण का प्रभाव–संगठन के उद्देश्य-प्रबंध का सामाजिक दायित्व ।

2. आयोजन तथा निर्णय

आयोजन तथा निर्णयन की मूल संकल्पनाएं—प्रबंध के अन्य कार्यों से उनका संबंध—आयोजन तथा निर्णयन के तत्व, तकनीक तथा प्रक्रिया–आयोजन तथा निर्णयन के प्रकार–आयोजन तथा निर्णयन का कार्यान्वयन ।

3. संगठन तथा कर्मचारी भर्ती

संगठन तथा कर्मचारी भर्ती की मूल संकल्पनाएं–संगठन का संरचनात्मक रुपांकण तथा उसका महत्व, विभागीकरण, नियंत्रण की विस्तृत प्रत्यायोजन, केन्द्रीयकरण, अनुक्रम प्रबंधक इत्यादि संगठन की पारम्परिक एवं अर्वाचीन संरचनाएं-संगठन तथा कर्मचारी भर्ती के सिद्धान्त, लेखाकरण एवं वित्तीय प्रकार्यों में उसका अनुप्रयोग, डाटा संकल्पनाएं क्षेत्र, अभिलेख मिसिल तथा मिसिल संरचना ।

4. निर्देशन तथा नेतृत्व

मूल संकल्पनाएं तथा तकनीक, संप्रेषण, अभिप्रेरण तथा नेतृत्व, प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण-संगठनात्मक व्यवहार की संकल्पना, सिद्धान्त तथा अनुप्रयोग ।

5. नियंत्रण तथा समन्वय

नियंत्रण तथा समन्वय की मूल संकल्पनाएं, तत्व प्रक्रिया एवं तकनीक ।

खण्ड ख–इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के मूल तत्व

(50 अंक)

ज्ञान का स्तर—बुनियादी जानकारी

उद्देश्य : इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के स्थूल स्वरूप तथा मूल तत्वों की जानकारी तथा गुण विवेचन सुनिश्चित करना ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. डाटा प्रोसेसिंग के तत्व—डाटा, सूचना आगत, (इनपुट) संसाधन (प्रोसेसिंग) तथा उत्पाद (आउटपुट)

2. कम्प्यूटर्स तथा उनकी विशेषताएं, कम्प्यूटरों का संक्षिप्त इतिहास, कम्प्यूटर हार्डवेयर–कम्प्यूटर की आधारभूत संक्रियाएं–मुख्य ढांचे–लघु कम्प्यूटर्स–माइक्रो कम्प्यूटर्स ।

3. आगत उपकरण–चुम्बकीय टेप, चुम्बकीय डिस्क, फ्लोपी-डिस्क, एम० आई० सी० आर०, ओ० सी० आर०, वी डी० यू० आदि ।

– आउटपुट उपकरण–प्रिन्टर्स, वी० डी० यू०, कम्प्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्मिंग

– ट्रमिनल्स तथा डाटा कम्यूनिकेशन–नेटवर्कस,-डिस्ट्रिब्यूटिड सिस्टम्स

– सोफ्टवेयर–सिस्टम्स, अनुप्रयोग साफ्टवेयर, स्पेसिफिकेशन सोफ्टवेयर

– इलैक्ट्रोनिक स्परेड शीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

– डाटा रिप्रेजैंटेशन–वाईनरी, बी० सी० डी० ओक्टल हैक्साडेसीमिल, ई० बी० सी० डी० आई० सी० तथा ए० एस० सी० आई० आई०

– कम्प्यूटर मैमोरी के प्रकार, कोर, सेमीकंडक्टर, आर० ए० एम०, आर० ओ० एम० बबल, मैमोरी एड्रेसिंग से सम्बन्धित संकल्पनाएं ।

4. कम्प्यूटर प्रोसेसिंग तकनीक, बैच प्रोसेसिंग, ऑन लाईन प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, वास्तविक टाइम प्रोसेसिंग, डाटा बेस डिस्ट्रिब्यूटिड बनाम सैन्ट्रलाइज्ड डाटा बेस के विशेष लक्षण ।

व्यावसायिक कम्प्यूटरों से संबंधित कम्प्यूटर टैक्नोलोजी में अति आधुनिक उन्नति :

5. फ्लोचार्टस से परिचय सिस्टम्स फ्लोचार्टस, रन फ्लो चार्टस, प्रोग्राम फ्लो चार्टस, उदहारण, लाभ तथा परिसीमाएं

6. कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से परिचय, कम्प्यूटर भाषाओं की सोपानिकी बोबेल तथा बेसिक भाषाओं का प्रयोग करते हुए साधारण प्रोग्रामिंग लेखन ।

(iii) पैराग्राफ 3 के अंत में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ें, जैसे :—

3क—अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तथा पाठ्यक्रम

ग्रुप I

प्रश्नपत्र 1—उच्चस्तरीय लेखाविधि

(एक प्रश्न पत्र—तीन घटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : विशेष ज्ञान

उद्देश्य : विद्यार्थियों की लेखाविधि संबंधी व्यावसायिक स्तर, सिद्धान्त एवं प्रक्रिया तथा विभिन्न व्यवहारिक स्थितियों में उनके अनुप्रयोग की क्षमता को जांचना ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. कम्पनी लेखाकरण की उच्चस्तरीय समस्याएं

2. संलयन, अंतर्लयन तथा पुनर्रचना की उच्चतर समस्याएं

3. कारोबार तथा शेयरों का मूल्यांकन

4. नियंत्रक कम्पनी के समकित लेखे

5. लेखाकरण का स्तर, विभिन्न लेखों संबंधी पक्षों पर संस्थान द्वारा जारी किए गए विवरण तथा निर्देशात्मक टिप्पणियां तथा उपरोक्त विषयों के संदर्भ में उनका अनुप्रयोग ।

6. लेखाकरण में विकास, मुद्रास्फीती समायोजित लेख, मानव संसाधन लेखाकरण, सामाजिक लेखाकरण एवं मूल्य सहित विवरण ।

7. आर्थिक विवरणों की परिसीमाएं—आर्थिक डाटा के अर्थ निर्णय तथा विश्लेषण सहित आर्थिक विवरणों का अर्थ निर्णय एवं विश्लेषण, अनुपातिक विश्लेषण, दो विभिन्न अनुपातों द्वारा प्रति जांच, अनुपातों की परिसीमाएं, विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण तथा अंत: प्रतिष्ठान तुलना ।

8. नकदी प्रवाद, निधि के उद्गम तथा अनुप्रयोग संबंधी विवरण ।

9. गैर लाभार्जन करने वाली संस्थाओं तथा जन सेवाओं के लेखाकरण के विशेष लक्षण ।

प्रश्नपत्र 2—प्रबंधक लेखाकरण एवं वित्तीय विश्लेषण

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : विशेष ज्ञान

उद्देश्य : यह जांच करना कि क्या विद्यार्थियों ने सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित संगठनों के प्रबंध लेखाकरण तथा संबंधित प्रबंध संबंधी निर्णयन की संकल्पनाओं तथा तकनीक की जानकारी प्राप्त कर ली है ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. वित्तीय प्रबंध का अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य—प्रबंधक के कार्य

2. अल्पावधि तथा दीर्घावधि वित्तीय आयोजन तथा पूर्वानुमान

प्रारम्भिक औद्योगिक बीकारी का पूर्वकथन—प्रचालन तथा वित्तीय लीवरेज लागत आयतन लाभ विश्लेषण ।

3. चालू पूंजी का प्रबन्ध—रोकड़ प्रबन्ध होने वाली प्राप्तियों का प्रबंध सूची प्रबंध और धन लागाना या चालू पूंजी

4. दीर्घावधि तथा अल्पावधि—वित्त व्यवस्था केश्रोत, बोनस शेयरों सहित पूंजी जारी करने पर नियंत्रण, पूंजी संरचना, अंश लाभ की नीति—पट्टा वित्त व्यवस्था—शेयरों तथा प्रतिभूतियों का जारी करना, प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना

5. पूंजी का बजट बनाना—परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना वित्तीय प्रक्षेपण — पै बैक प्रणाली सहित पूंजीगत परियोजनाओं के मूल्यांकन की तकनीक—प्रतिफल की दर—बट्टागत नकद प्रवाह—वर्तमान मूल्य तथा आंतरिक प्रतिफल की दर प्रणालियां—पूंजी न्याय बाटन (राशनिंग) पूंजीगत बजट बनाने में तथा जोखिम निवेश में जोखिम विश्लेषण— सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, पूंजी के बजट नियंत्रण में नेटवर्क तकनीक पी० ई० आर० टी० तथा सी० पी० एम०

6. पूंजी की लागत—पूंजी के विभिन्न स्त्रोतों की लागत—पूंजी की भारित औसत लागत—पूंजी की सीमान्त लागत ।

7. बजट तथा बजट नियंत्रण—मूल बजट की ओर अग्रसर होने के लिए उत्तरदायित्व बजट समेत प्रकार्यात्म बजट, नियम तथा नम्य बजट—निष्पादन बजट शून्य आधारित बजट बनाना, विभिन्न स्तरों पर निष्पादन प्रतिवेदन करना ।

8. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से सर्वाधिक कर्जों की बातचीत करना भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सर्वाधिक कर्जों की समीक्षा ।

9. निवेश विभाग का प्रबंध—प्रतिभूतियों का चुनाव—बेचने तथा खरीदने के निर्णय का समय ।

10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रबंध के विशेष लक्षण ।

11. मुद्रास्फीती तथा वित्तीय प्रबंध

12. निर्गमित कर व्यवस्था तथा उसका निर्गमित वित्त व्यवस्था पर प्रभाव

13. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध से परिचय—अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साधन जुटाना तथा विनिमय दर—जोखिम, प्रबंध, विदेशी मुद्रा में सौदे ।

प्रश्नपत्र 3—एडवांस्ड एवं मैनेजमेंट आडिटिंग

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ स्तर

उद्देश्य : यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने चालू लेखा परीक्षण प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया है और क्या वे उन्हें विविध प्रकार की व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. लेखा परीक्षण का आयोजन तथा कार्यक्रम बनाना लेखा परीक्षण कार्य के प्रवाह का आयोजन अन्तरिम लेखा परीक्षण, अंतिम लेखा परीक्षा, सहायकों के विभिन्न स्तरों के बीच काम बंटवारा—पर्यवेक्षण की समस्याएं—लेखा परीक्षण टिप्पणियों तथा कार्यपत्रों का पुनर्निरीक्षण प्रधान का अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन का प्रश्न लेखा परीक्षण कार्य गुणवत्ता पर नियंत्रण, अन्य लेखा परीक्षक/आन्तरिक लेखा परीक्षक/किसी विशेषज्ञ पर विश्वास ।

2. आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया का मूल्यांकन—प्रश्नावली तथा प्रवाह चार्ट सहित तकनीक आन्तरिक तथा वाह्यक लेखा परीक्षण, दोनों में समन्वय ।

3. विशेष लेखा परीक्षण तकनीक

चयनात्मक सत्यापन, सांख्यिकीय नमूना चयन—विशेष लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं—परिसंपत्ति के भौतिक उत्पादन की साक्षी करना, देनदारों तथा लेनदारों का सीधा वृतुलीकरण (सरकुलाइजेशन)

खातों का सकल आधार पर पुनर्निरीक्षण—वित्तीय स्थिति विवरण का लेखा परीक्षण—अनुपात विश्लेषण आदि, लेखा परीक्षण की कार्य पटुता में सुधार—पद्धति लेखा परीक्षण एवं जोखिम आधारित शेख परीक्षण ।

4. सीमित दायित्व वाली कम्पनियों का लेखा परीक्षण

(क) लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व बनाम

(1) कम्पनी नियम के अन्तर्गत संवैधानिक उत्तर दायित्व ।

(2) शाखाओं का लेखा परीक्षण

(3) संयुक्त लेखा परीक्षण

(ख) कम्पनियों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में सत्य तथा उचित एवं महत्वपूर्णता की संकल्पनाएं,

(ग) प्रबंध से सूचनाएं तथा व्याख्याएं प्राप्त करने का महत्व तथा उन पर विश्वास करने की मात्रा

(घ) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन—शर्तें खातों पर टिप्पणियां, खातों पर टिप्पणियों तथा शर्तों में अंतर, प्रबंधकों को संवैधानिक लेखा का परीक्षण द्वारा विस्तृत लेखा टिप्पनी बनाम सदस्यों को सूचित करने का दायित्व विवरण पत्रिका के लिए विशेष प्रतिवेदन ।

(च) अंश लाभ तथा विभाज्य लाभ मूल्यह्रास के विशेष संदर्भ में वित्तीय विधिक तथा नीति संबंधी अनुचिंतन ।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा परीक्षण में विशेष बिन्दु—धारा 619 के अन्तर्गत कम्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल द्वारा दिए गए निर्देश औचित्य तथा कार्य क्षमता लेखा परीक्षण की संकल्पनाएं

6. विशेष लेखा परीक्षण

7. लागत शेखा परीक्षण

8. प्रमाणीकरण

बोनस की अदायगी नियम/आयात/निर्यात प्राधिकारियों के अन्तर्गत दिए गए प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन का अंतर, गैर लेखा परीक्षण ग्राहकों को निर्दिष्ट सेवा

9. अन्वेषण

अंतर्लयन पुर्नसंरचना तथा कारोबार के बेचने खरीदने जैसी योजनाओं के संदर्भ में अन्वेषण ।

10. आयकर नियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत लेखा परीक्षण ।

11. बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा सहकारी समितियों के लेखा परीक्षण का विशेष अभिलक्षण

12. विवरण/मानक तथा निर्देशन टिप्पिणयां, लेखाकरण मान, लेखाकरण तथा लेखा परीक्षण के मामलों से संबंधित संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षण संबंधी पृथाओं पर विवरण तथा निर्देशन टिप्पणियां—साधारणतया स्वीकृत लेखा परीक्षण पृथाओं की संकल्पना और उनके संदर्भ में लेखा परीक्षण तथा उसका महत्व ।

13. लेखा परीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व—अन्य पक्ष के प्रति दायित्व प्रकृति तथा सीमा ।

14. वृत्तक नीति शास्त्र तथा व्यवहार संहिता ।

15. संक्रियात्मक प्रबंध एवं लेखा परीक्षण की संकल्पना—इसकी प्रकृति एवं उद्देश्य संगठन लेखा परीक्षण कार्यक्रम—व्यावहारात्मक समस्याएं

16. आंतरिक नियंत्रण का पुर्ननिरीक्षण, क्रय संक्रिया, विनिमय, परिचालन, विक्रय तथा वितरण, कार्मिक नीतियां, प्रणाली तथा प्रक्रिया समेत प्रबन्ध एवं प्रचालन लेखा परीक्षण के निर्दिष्ट क्षेत्र ।

17. बैंक से ऋण लेने वालों का लेखा परीक्षण, स्टाक एक्सचेंज के दलालों का लेखा परीक्षण जैसे विशेष लेखा परीक्षण नियम कार्य ।

18. संगणक लेखा परीक्षण, ई० डी० पी० लेखा परीक्षण की विशिष्ट समस्याएं, आंतरिक नियंत्रण, विशेषतया प्रक्रिया नियंत्रण तथा सुविधा नियंत्रण के पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता, ई० डी० पी० निर्गत के लेखा परीक्षण की तकनीक आंतरिक तथा प्रबन्ध लेखा परीक्षण उद्देश्यों के लिए संगणक का प्रयोग—जांच गड्ढिया (टैस्ट पैक्स) संगणकीय लेखा परीक्षण कार्यक्रम, संगणक पद्धति को लागू समय लेखा परीक्षक की अंतर्भावितता ।

प्रश्नपत्र—निगमित नियम एवं सचिविक प्रैक्टिस

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य : विद्यार्थी की कम्पनी अधिनियम तथा संबंधित कानूनों की तथा उनके व्यावहारिक प्रयोग की जानकारी की जांच करना ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. दि कम्पनीज एक्ट 1956 (धारा 146 के अंत तक)
2. दि मोनोपोलिस एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसिस एक्ट 1969
3. दि फोरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973
4. दि कैपीटल इशूज (कन्ट्रोल) एक्ट 1947 तथा उसके अधीन जारी किए गए छूट के आदेश
5. दि सिक इंडस्ट्रीज कम्पनी (स्पैशल प्रोविजन्स) एक्ट 1985
6. कानून विलेश एवं प्रलेश के अर्थ निरूपण के नियम
7. सचिविक पद्धति एवं अभ्यास का अभिकलन ।

ग्रुप—II

प्रश्नपत्र 5—उच्चस्तरीय लागत श्रोताविधि एवं लागतविधि

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

जानकारी का स्तर : विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य : विद्यार्थियों की लागत लेखा विधि के सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया की समझ तथा प्रबंध संबंधी निर्णयन के लिए विभिन्न स्थितियों में उनका प्रयोग करने की क्षमता की जांच करना ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. लागत वर्गीकरण एवं विशेषण

2. निर्णयन में लागत संकल्पना—संगत लागत, विभेद लागत, वर्तमान लागत, तथा विकल्प लागत ।

3. सामान्य लागत—सीमान्त लागत एवं अवशोषण लागत का अंतर, संतुलन स्तर विश्लेषण, लागत आयतन, लाभ विश्लेषण संतुलन स्तर चार्ट, अंशदायी, सीमा तथा निर्णयन से संबंधित समस्याएं जैसे—"बनाए या खरीदे", कामबंदी जा जारी रखना "विस्तार या संकोचन", विशेष अवस्थाओं में मूल्य निर्धारण, उत्पाद संबंधी निर्णय ।

4. निर्णयन की समस्याएं जैसे, "रखें या बदले", "मरम्मत करवायें या नया बनाएं", "अभी या बाद में", "परिवर्तन अथवा पूर्वत", "बेचे या प्रक्रिया करें", "अपना खरीदे या किराए पर लें", "बेचे या रद्दी कर दे या रखें", "मूल्य संबंधी निर्णय, उत्पाद संबंधी निर्णय, विपणन तथा वितरण संबंधी निर्णय, उत्पाद विकास, प्रतियोगात्मक मूल्य निर्धारण, विभेदक मूल्य तथा बट्टे तथा मूल्य निर्धारण/विपणन दाँवपेच ।

5. लागत निर्धारण से भिन्न, लागत नियंत्रण छीजन पर नियंत्रण, रद्दी, रद्दी उत्पाद तथा दोषपूर्ण उत्पाद ।

6. प्रबंध नियंत्रण—उत्तरदायित्व लेखाकरण, लागत, लाभ तथा निवेश केन्द्र, अंशदान दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए स्थानांतरण मूल्यांकन की समस्याएं ।

7. मानक लागत निर्धारण तथा प्रसरण विश्लेषण, सामग्री, श्रम तथा उपरिव्यय, प्रसरण का समाधार लेखन ।

8. लागत में कमी—लागत कमी के तकनीक जैसे कार्य अध्ययनय समय तथा गति अध्ययन एवं मूल्य विश्लेषण ।

प्रश्नपत्र 6—पद्धति विश्लेषण आधार सामग्री का संसाधन तथा परिमाणनीय तकनीक

(एक प्रश्न पत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : (1) विद्यार्थियों की पद्धति विश्लेषण तथ अभिकलन की तकनीक को व्यवसाय में संगणक के प्रयोग का अभिकलन तथ कार्यान्वित करने की योग्यता की जांच करना ।

(2) विद्यार्थियों की परीमाणनीय तकनीक को व्यवसाय की समस्याओं में प्रयोग करने की योग्यता की जांच करना ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. एम० आई० एस० की आधारभूत आवश्यकताएं—इसकी आवश्यकता, उद्देश्य तथा सार्थकता, प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता की मान्यता प्रबंध की समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण, हर व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष रूप से अभिकलित सूचनाव्यवस्था संस्थापित करने की आवश्यकता निर्णयन के लिए यूना के प्रयोग का संकल्पनात्मक ज्ञान ।

2. व्यवस्था विकास प्रक्रिया

3. व्यवस्था विश्लेषण तथा अभिकलन, कार्यक्रम बनाने की प्रणालियां, तकनीक तथा उपकरणों की संकल्पनाएं ।

4. शारीरिक . संगणीकीय व्यवस्था में परिवर्तन, संबंधित समस्याएं एवं मूल्यांकन ।

5. संगणकीय व्यावसायिक प्रयोगों का अभिकलन, वित्तीय लेखाकरण, सूची नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, अंश (शेयर) लेखाकरण वेतन बिपत्र तैयार करना एवं लेखाकरण बिक्री लेखाकरण, बीजक बनाना ।

6. संगणक प्रबंध—ई० डी० पी० विभाग का संगठन तथा भर्तीकरण

7. संगणक का चुनाव एवं संस्थापन संगणक का चुनाव, चुनाव की कसौटी, विविदाओं का मूल्यांकन, वित्तीय मामले, (किराया, पट्टा, क्रय संस्थापन, व्यय, संगणक केन्द्र)

8. ई० डी० पी० व्यवस्था का नियंत्रण ।

9. मानक-प्रबंध, प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं

10. संगणक व्यवस्था की सुरक्षा, वैकल्पिक सुविधाएं अग्नि के खतरे से रक्षा, अग्नि का पता लगाने तथा बुझाने के उपकरण, अग्नि लग जाने की दशा में उठाए जाने वाले पग, ऐसी स्थिति में आधार सामग्री को कैसे बचाया जाए, बीजक संरक्षण ।

11. परिमाणीय तकनीक-रेखीय कार्यक्रम बनाना, परिवहन, थिम कार्य की समस्याएं पर्ट तथा सी० पी० एम०

सांख्यिकीय निर्णयन प्रमेय, ई० डी० पी० आई० द्विपद तथा साधारण प्रकार्यों का प्रयोग करते हुए पर—विश्लेषण (पोस्टीयरपर एनेलाइसिस क्यूईग प्रमेय एक सारणी (सिंगल चैनल, अनुरूपण (सिमुलेशन)

प्रश्न पत्र 7—प्रत्यक्ष कर

(एक प्रश्न पत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य : (1) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों ने आयकर नियम 1961 संपत्ति कर नियम 1957, उपहार कर नियम 1958 और संबंधित नियम तथा अग्रणी मामलों से उत्पन्न सिद्धान्तो का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

(2) यह जांचना कि क्या विद्यार्थियों में वास्तविक व्यवहार की विभिन्न परिस्थितियों में विशेषतय उन क्षेत्रों के संदर्भ में जहां कर योजना किया जा सकता है, कानून के उपबंधों को योग करने की योग्यता है ।

विस्तृत विषय वस्तु

1. आयकर अधिनियम 1961

2. सम्पत्ति कर अधिनियम 1957

3. उपहार कर अधिनियम 1958

प्रत्यक्षकर संबंधित नियमों का प्रावरण करते समय विद्यार्थी स्वयं को कर आयोजन संबंधित विभिन्न विचारों से सुपरिचित कर लें । इसमें निर्दिष्ट प्रबन्ध निर्णयों से संबंधित कर अभिचिंतन, विदेशी सहयोग समझौते अंतर्लयन, कर प्रकृष्ट कार्मिक क्षतिपूर्ति योजनाएं, करों से अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए पालन की जाने वाली लेखाविधि की तथा अन्य पूर्वाविधान सम्मिलित है ।

प्रश्नपत्र 8—अप्रत्यक्ष कर

(एक प्रश्नपत्र—तीन घंटे—100 अंक)

ज्ञान का स्तर :कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य : यह जांचना कि विद्यार्थियों ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा तटकर का नियंत्रण करने वाले नियमों के मूलभूत सिद्धान्तों का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

विस्तृत विषय वस्तु

अद्यतन संशोधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 अद्यतन संशोधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 तटकर तथा उत्पादन शुल्क राजस्व अपील अधिकरण अधिनियम 1986 ।

1. सीमा शुल्क का स्वरूप—विद्यार्थी इतिहास, व्याप्ति आदि केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत सीमा शुल्क का उदग्रहण तथा संचयन अधिसूचनाओं, प्रशुल्क जानकारी तथा व्यापारिक नोटिस के कानूनी प्रभाव ।

2. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण तथा निष्कापण का नियंत्रण करने वाले

केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944, केन्द्रीय सीमा शुल्क (मूल्यांकन नियम 1975) के अन्तर्गत मूल्यांकन तथा मूल्य सूचियों का अनुमोदन ।

3. अर्थनिर्धारण तथा वर्गीकृत सूचियों के फाइल करने तथा अनुमोदन के नियमों के संदर्भ में केन्द्रीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1988 के अन्तर्गत वस्तुओं का वर्गीकरण

4. अनन्तिम कर निर्धारण सहित कर निर्धारण, स्वय निष्कासन प्रक्रिया, ड्यूटी का भुगतान तथा ड्यूटी की दर, अभिलेख पर आधारित नियंत्रण तथा उत्पादन पर आधारित नियंत्रण ।

5. कम उदग्रहण का न होना, गलती से धन वापसी की मंजूरी—अधिक ड्यूटी का भुगतान, धन की वापसी तथा कम उदग्रहण या उदग्रहण के न होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के अधिकार ।

6. लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया—औपचारिकताएं तथा संबंधित बंधपत्र ।

7. उत्पादन शुल्क वाले माल के भंडारण से संबंधित प्रक्रिया, ड्यूटी के भुगतान का समय एवं प्रणाली, माल को चिह्नित करने के नियम, माल के निष्कासन से संबंधित द्वारपत्र तथा अन्य मामले ।

8. अभिलेखों तथा रजिस्ट्री का रख रखाव तथा विवरणी का फाईल करना ।

9. ड्यूटी दिए हुए माल का कारखाने में प्रवेश तथा प्रतिधारण ।

10. विशेष औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए गए माल पर राजस्व की माफी ।

11. निर्यात के लिए राजस्व की वापसी (ड्यूटी ड्रा बैक) की प्रक्रिया ।

12. प्रोफार्मा क्रेडिट तथा मोडवेट ।

13. विभागीय संगठन संरचना—अधिनिर्णयन तथा अपील की प्रक्रिया, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण असली अधिकरण तथा उत्पादन राजस्व अपील अधिकरण)

14. अपराध तथा दन्ड

15. लघु उद्योगों के लिए छूट

11. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

1. सीमा शुल्क के उद्ग्रहण तथा छूट के नियंत्रण करने वाले सिद्धान्त

2. माल के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के आधार भूत सिद्धान्त

3. सीमा शुल्क प्राधिकारी, सीमा शुल्क पत्तन, भंडार स्टेशनों, आदि की नियुक्ति

4. माल के आयात तथा निर्यात उपबन्ध करने वाले उपबंध, बैगेज, डाकद्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं तथा भंडार से संबंधित विशेष उपबन्ध ।

5. माल के लाने ले जाने तथा भंडार में संबंधित विस्तृत प्रक्रिया

6. भुगतान की हुई सीमा शुल्क की वापसी

ए० के० मजूमदार,
सचिव

टिप्पणी :—

1. चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, विनियम 1988, 1 जून 1988 को प्रकाशित भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 1 जून, 1988 की इंस्टीट्यूट की अधिसूचना संख्या 1-सी० ए (7)/134/88 के अन्तर्गत प्रकाशित हुए थे ।

2. इन विनियमों में किये गये संशोधनों का विवरण जो कि भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किये गये है, निम्न प्रकार है :—

1. विनियम 48 में संशोधन—7 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी० ए० (7)/1/89 दिनांक 25 सितम्बर, 1989 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये ।

2. विनियम 159 में संशोधन—19 जनवरी के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी०ए०(7)/10/90 दिनांक 2-1-1991 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये ।

3. विनियम 6, 34 एवं 39 में संशोधन—19 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी० ए० (7)/11/90 दिनांक 4 जनवरी, 1991 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये ।

4. विनियम 190 में संशोधन—2 फरवरी 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 1-सी०ए०(7) 13/90 दिनांक 14 जनवरी, 1991 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये ।

5. विनियम, 86, 87, 92, 97, 111, 112 और 157 में संशोधन—2 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी०ए०(7)/12/91 दिनांक 12 फरवरी, 1991 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 1992

सं० बी-33 (13)-17/86-स्था०-4—क्षेत्रीय बोर्ड, पश्चिमी बंगाल के पुनर्गठन के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 3-10-1991 की क्रम सं० 6 पर दी गई मौजूदा प्रविष्टि को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

6. श्री ए० बी० चौधरी, श्रम सलाहकार, इंडियन चैम्बर आफ कामर्स 4 इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-700001	नियोजकों के प्रतिनिधि

(श्रीमती) कुसुम प्रसाद,
महानिदेशक

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली-1100001, दिनांक 17 फरवरी 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग 1/495—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार

के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट को समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके और छूट दी है	के० भ० नि० आ फाइल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स अहमदाबाद मैन्यूफेक्चरिंग एण्ड कालीको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड (कालीको मिल्स) जमालपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद	जी०/जे०/279	2/1959/डी०एल०आई०/एक्जम/89/पार्ट-I/2927 दिनांक 18-3-90	17-9-91	18-9-91 से 17-9-94	2/644/82-डी एल० आई०
2.	मैसर्स गुजरात मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, पी० बी० नं० 1 कर्मसाद 388325 (गुजरात)	जी०/जे०/4499	एस-35014/280/83 11 (एस एस II) दिनांक 2-6-86	23-12-89	24-12-89 से 23-12-92	2/961/83-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स तापती इन्डस्ट्रियल इंजीनियरस मनकुण कम्पाउन्ड, ऐ० के० रोड़, सूरत-395008	जी०/जे०/16714	2/1959/डी० एल० आई०/89/एक्जम/पार्ट-I/3914 दिनांक 1-8-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/2761/90-डी एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ

बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/503—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, वी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, ताकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, वी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-2) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्री भविष्य निधि आयुक्त ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स पी० एम० जी० इन्डस्ट्रियल इंस्टीटूयूट पीलमेडु, कोयम्बटूर-641004	टी एन 88	1-12-88 से 30-6-90	2/3966/92-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स ओरियंटल टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज, आई० एम० एम० सी० कैम्पस ईस्ट मेन रोड, मेटूर एम-636401 (सलम जिला)	टी० एन०/17088	1-1-90 से 28-2-90	2/3965/92-डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जायें, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ायें जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदत्त होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/511—जहां मैसर्स थोमसले मेट्रेक्स होबर्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस वर्कस, 26/ए, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, पटान्चेरी, 502319, डिस्ट्रीक मेडक, आन्ध्रा प्रदेश (कोड सं. ए. पी./5726) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/पीटी-1/1128 दिनांक 19-12-89 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में

निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 1-3-92 से 28-2-95 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-95 भी शामिल है।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्विष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यकता प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग 1/519—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम तथा पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड, 14, नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता–700001	डब्ल्यू० बी/13356	1–5–90 से 20–4–93	2/3923/91–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (तीसरी मंजिल) 14/1बी ऐजरा गली कलकता–700001 (उसके संघीय विभाग सहित 2, दिल्ली बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में) उपक्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बंगलौर, जलन्धर और विदेशी कार्यालय एटकोटडी इवोइर यू० एस० ए०, यू० ए० ई० ईमरामन्नसटर और आस्ट्रेलिया ग्रेड ब्रिटेन ला जयेगल केन्या सिंगापुर	डब्ल्यू० बी/15617	1–3–90 से 28–2–93	2/3922/91–डी० एल० आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधि वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 18 फरवरी 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/527—जहां मैसर्स डोमीनेंट ऑफसैट (प्रा.) लिमिटेड, पालम गुड़गांव रोड, गुड़गांव (कोड नं. एच. आर./10633) हरियाणा ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं—दिनांक 1-5-91 से 30-4-94 तक।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/535—जहां मैसर्स मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड, ओल्ड एग्जीबीशन ग्राउन्ड तरातला रोड, कलकत्ता-700088 (कोड संख्या डब्ल्यू बी/15281) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या : एस-35014/104/87/पी. एफ. II (एस. एस II) दिनांक 3-4-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 16-10-88 से 15-10-91 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 15-10-91 भी शामिल है ।

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमीयम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा. जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निगम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/543—जहां मैसर्स पंजाब सिरामिक्स लिमिटेड, पी. बी. नं. 36, दाब्बली रोड, 151001 (पंजाब) भटिन्डा (कोड सं. पी. एल./10557) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त चन्डीगढ़ ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। (दिनांक 1-3-90 से 28-2-93 तक)।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो, जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 19 फरवरी 1992

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/551—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	पहले से प्रदान की छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स एसकार्टस ट्रेक्टर्स लिमिटेड 11, स्काइलिंडया हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001	डी०एल०/2676	2/1959/डी०एल०आई०/एक्जम/89/पार्ट–1 दिनांक 20–10–89	30–11–90	1–12–90 से 30–11–93	2/1086/89-डी०एल०आई०
2.	मैसर्स के० एल० राठी स्टील्स लि०, लोनी रोड़, शाहदरा, दिल्ली–32	डी० एल०/3365	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1 दिनांक 20–10–89	7–11–91	8–11–91 से 7–11–94	2/607/81–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स सचदेवा प्राइवेट लिमिटेड 69/1 ए, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015	डी०एल०/3681	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–I दिनांक 28–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2095/89–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स सचदेवा टैक्सटाइल्स प्रा० लिमिटेड, 69/1 ए, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015	डी०एल०/6617	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1 दिनांक 18–11–89	31–7–90	1–8–90 से 31–7–93	2/328/90–डी० एल० आई०

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है)। सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों का प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/559—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० व तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट को समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1.	मैसर्स कर्नाटका सिल्क इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट सन सिल्क मिल्स, चन्नापटना 571501	के०एन०/47	एस-35014/220/86/एस० एस० II, दिनांक 20-8-86	19-8-89	20-8-89 से 19-8-92	2/1471/86-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स सुजाता टैक्सटाइल्स मिल्स पो० आ० ननजनगुड कर्नाटका-371301	के०एन०/89	एस-35014/285/85/एस० एस० -IV दिनांक 25-11-85	24-11-88	25-11-88 से 24-11-91	2/763/82-डी० एल० आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा पीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/567—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० और तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स हि० पावर आटोमैटिक पार्ट्स प्रा० लि०, डी० 30, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, अम्बातुर, मद्रास–58	टी०एन०/10788	2/1959/डी०एल०आई०/ एक्जाम/89–भाग–1/6103 दिनांक 10–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2816/90–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स सुन्दरम पिनास लि० 21, पटुलोस रोड, मद्रास–2 (तथा इसकी सभी शाखाएं जो इस कोड नं० में स्थित है)	टी०एन०/10595	–वही– दिनांक 10–7–91	19–11–91	20–11–91 से 19–11–94	2/1308/85–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स सऊदरन सविसगियर लि० प० ब० 114, अवदी रोड, अम्बतुर मद्रास–600058	टी एन०/3469	एस–35014(73)82/ पी०एफ० II/एस एस–II दिनांक 2–9–86	29–10–88	30–10–88 से 29–10–91	2/503/81–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स के० एच० सुज लिमिटेड, बाई पास रोड, रानीपेट–632401 नार्थ अरकोट जिला	टी०एन०/19687	2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जाम/89/भाग–1/ दिनांक 18–9–89	31–1–91	1–2–91 से 31–1–94	2/2040/89–डी० एल० आई०
5.	मैसर्स कारबोरण्डम यूनिवर्सल लिमिटेड, 28 राजा जी रोड, मद्रास–600001	टी० एम०/860	एस–35014/171/85 एस० एस० II दिनांक 28–6–85	27–6–88	28–6–88 से 27–6–91	2/1246/85–डी० एल० आई०
6.	मैसर्स पोंडस (इंडिया) लिमिटेड 26, सी–इन–सी रोड, मद्रास–600105	टी० एन०/5394	एस–35014/418/82/ पी एफ II एस एस II दिनांक 9–7–87	31–12–88	1–1–89 से 31–12–91	2/286/79–डी एल आई

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) । सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन प्रोद्भूत हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय

भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/575—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० और तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स स्टैण्डर्ड पैकिंरज, 6–6 असीड प्रा० इन्डस्ट्रियल एस्टेट, नैलोर–524004	ए०पी/6980	2/1959/डी० एल० आई०/89/भाग–I/602 दिनांक 15–9–89	28–2–91	1–3–91 से 28–2–94	2/1997/89–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स शांति मार्किटिंग एंड सर्विस प्रा० लि०, 7–1–25, ग्रीन लैंडस अमीरपेट, हैदराबाद–500016 (आ प्र)	ए०पी /16950	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/भाग–I/1616 दिनांक 13–9–91	31–1–92	1–2–92 से 31–1–95	2/3801/91–डी० एल० आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भविष्य जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Bombay, the 7th March 1992

In pursuance of rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954] the following list (for the quarter ended 31st March 1991) is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the chief Accountant, Reserve bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Bombay :—

Number of Security	Value Rs/Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name of the claimant(s) for issue of duplicate and or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		LIST "A"			
		CALCUTTA CIRCLE			
		3% Conversion Loan, 1946			
CA 322828	11,700	Reserve Bank of India	15-9-1980	Chief Manager Bank of India, Chowringhee Square Branch, Calcutta, on behalf of Lalita Roy.	Jt. Manager's order dated 8th January 1991 Dy. No. LCO-159/90-91 dated 9th January 1991 File No. I. 2445 case No. 846.
CA 299491	1,100	Kamala Sengupta	15-9-1977	Do.	Do.

Sd/-Illegible
Chief Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 21st February 1992

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/19/92.—Whereas a draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1988 were published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (39 of 1949) at pages 2897 to 2908 of the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 21st September, 1991 under the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No. 1-CA(7)/19/91 dated the 4th September, 1991;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 25th September, 1991;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India and approved by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1989, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988 :—

I. For, regulations 23, 24, 25 and 26, the following regulations shall be substituted, namely :—

23. *Admission to the Entrance Examination, Fees and Syllabus*

(1) No candidate shall be admitted to the Entrance Examination unless he is a graduate within the meaning of clause (ix) of sub-regulation (1) of regulation 2 or is undergoing the graduation course.

Provided that a candidate who having appeared at the Entrance Examination held after 1st January, 1985 has failed in the said examination on three occasions shall not be admitted to the Entrance Examination.

(2) A candidate for admission to the Entrance Examination shall pay such fee as may be fixed by the Council from time to time.

(3) A candidate for admission to the Entrance Examination shall be examined in the subjects prescribed in paragraph 1 of Schedule 'B'.

(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, at any time after the commencement of registration for the Foundation Course, discontinue the Entrance Examination.

24. *Registration for the Foundation Course*

(1) No candidate shall be registered for the Foundation Course unless he has passed the Senior Secondary Examination conducted by an examining body constituted by law in India for an examination recognised by the Central Government as equivalent thereto.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a person who has appeared in the final Senior Secondary

Examination or an examination recognised by the Government or the Council as equivalent thereto may also be provisionally registered for the Foundation Course by the coaching organisation set-up under the control and supervision of the Council.

Provided that the provisional registration of a person shall be confirmed only after satisfactory proof has been furnished by him to the coaching organisation within a period of six months from the date of provisional registration of having passed the aforesaid examination.

Provided further that if such a person fails to produce such proof within the aforesaid period his provisional registration shall be cancelled and no part of the registration fee or the tuition fee paid by him shall be refunded and for the purpose of these regulations on credit shall be given for the theoretical instructions undergone.

(3) Before admission to the Foundation Course, a candidate shall pay such fee, as may be fixed by the Council from time to time.

25. (1) *Admission to the Foundation Examination, Fees and Syllabus*

No candidate shall be admitted to the Foundation Examination unless he produces a certificate from the head of the coaching organisation, to the effect that he is registered with the coaching organisation and has complied with the requirements of the postal tuition scheme.

Provided that commerce graduates who have passed the graduation examination with accountancy and auditing and mercantile law or commercial law, securing in aggregate a minimum of 50% of the total marks in the examination or graduates other than commerce graduates who have passed the graduation examination with mathematics as one of the subjects securing in the aggregate a minimum of 60% of the total marks in the examination or graduates other than commerce graduates who have passed the graduation examination with any other subjects other than mathematics securing in the aggregate a minimum of 55% of the total marks in the examination shall be exempted from passing the foundation Examination.

Provided further that they shall be permitted to register themselves as articled/audit clerks to receive practical training prescribed under these regulations, if found otherwise eligible.

Explanation :—For the purpose of this regulation, commerce graduate shall mean a graduate having passed the graduation examination with accountancy and auditing and mercantile law or commercial law as full papers, irrespective of any other subjects offered in the curriculum.

(2) A candidate for the Foundation Examination shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(3) A candidate for the Foundation Examination shall be examined in the subjects prescribed in Paragraph 1A of Schedule 'B'.

26. *Admission to the Intermediate Examination*

No candidate shall be admitted to the Intermediate Examination unless :—

(i) (a) he has passed the Entrance Examination and is a graduate within the meaning of clause (ix) of sub-regulation (1) of Regulation 2 or

(b) he has passed the Foundation Examination or is exempted from passing the said examination under these regulations; and

(ii) he has completed not less than nine months of service as an articled clerk or as an audit clerk or partly as an articled clerk and partly as an audit clerk, three months prior to the first day of the month in which the examination is held; and

(iii) he produces a certificate from the head of the coaching organisation to the effect that he has complied with the requirements of the postal tuition scheme :

Provided that the aforesaid certificate shall be valid for such period computed from the date of its issue as may be specified by the coaching organisation, whereafter the candidate shall have to obtain a fresh certificate after fulfilling such conditions as may be imposed by the coaching organisation in that behalf."

II. for regulations 28 and 29, the following regulations shall be substituted, namely :—

28. *Syllabus for the Intermediate Examination*

(1) A candidate for the Intermediate Examination held after 1st January, 1985 shall be examined in the groups and subjects prescribed in Paragraph 2 of Schedule 'B'.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, at any time after introduction of the Foundation Course, discontinue holding the Intermediate Examination and require the candidates to pass the Intermediate Examination as per the syllabus given in Paragraph 2A of Schedule 'B'.

29. *Admission to the Final Examination*

No candidate shall be admitted to the Final Examination unless :—

(i) he has either passed the Intermediate Examination under these Regulations or the Chartered Accountants Regulations, 1964, or the Intermediate or the First examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949, or was exempted from passing the First examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949; and

(ii) he has completed the practical training as is required for admission as a member or has yet to serve not more than nine months of practical training at least three months prior to the first day of the month in which the examination is held :

Explanation :—In computing the aforesaid period of nine months leave taken in excess of 138 days in the case of an articled clerk and 184 days in the case of an audit clerk shall be regarded as the period yet to be served under articled or audit service, as the case may be.

(iii) There has been a time interval of at least two Final Examinations between passing of the Intermediate Examination and the first appearance at the Final examination.

Provided that—

(i) in the case of a candidate who appears in the Final Examination within the last six months of the period of his practical training, there need be a time interval of only one final examination between the passing of the Intermediate Examination and the first appearance at the Final Examination; and

(ii) in the case of a candidate who appears in the Final Examination after completion of the period of his practical training, there need be no time interval between the passing of the Intermediate Examination and the first appearance at the Final Examination."

III. for regulation 31, the following regulation shall be substituted, namely :—

31. *Syllabus for the Final Examination*

(1) A candidate for the Final Examination shall be examined in the groups and subjects prescribed in paragraph 3 of Schedule 'B'.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, at any time after introduction of the Foundation Course, discontinue holding the Final examination as per the syllabus given in paragraph 3 of Schedule 'B' and require the candidates to pass the Final examination as per the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B'."

IV. for regulations 36, 37 and 38, the following regulations shall be substituted, namely :—

36. *Requirement for passing the Entrance Examination and the Foundation Examination*

(1) A candidate for the Entrance Examination shall ordinarily be declared to have passed in the examination if he obtains at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper and a minimum of 50 percent of the total marks of all the papers.

(2) A candidate for the Foundation Examination shall be declared ordinarily to have passed the examination if he obtains at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper and a minimum of 50 percent of the total marks of all the papers.

37. *Requirements for passing the Intermediate Examination*

(1) A candidate shall ordinarily be declared to have passed the Intermediate examination if he passes in both the groups and he may appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination and in the remaining group at any subsequent examination.

(2) A candidate shall be declared to have passed in both the groups simultaneously if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of both the groups and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a group if he secures at one sitting minimum of 40 percent marks in each paper of the group and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of that group.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Intermediate examination held under the scheme of examinations prior to the commencement of the examination under the syllabus given in paragraph 2A of Schedule 'B' of these regulations, shall be entitled to the exemption from appearing in the papers, specified in the following tables and he shall be declared to have passed the Intermediate examination if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each of the remaining papers and a minimum of 50 percent marks in the aggreate of all such remaining papers put together.

Provided a candidate who is exempted from appearing in five papers will be declared to have passed in the said examination if he secures a minimum of 50 percent marks in the remaining paper.

TABLE 'A'

Papers of the Intermediate examination passed under Schedule 'B' to the chartered Accountants Regulations, 1964	Exemption to which the candidate is entitled at any Intermediate examination under the syllabus given in paragraph 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988.
Group I	
Paper 1 : Accounting	Paper (1) : Advanced Accounting (Group I)
Paper 2 : Accounting	Paper (1) : Advanced Accounting (Group I)
Paper 3 : Auditing	Paper (2) : Auditing (Group I)
Group II	
Paper 4 : Cost Accounts & Statistics	Paper 4 : Cost Accounting (Group II)
Paper 5 : Mercantile Law & Company Law	Paper 3 : Corporate and Other Laws (Group I)
Paper 6 : General Commercial Knowledge	Nil

TABLE 'B'

Papers of the Intermediate Examination passed under Schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations, 1964 or under paragraph 2 of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988.	Exemption to which the candidate is entitled at any Intermediate Examination under the syllabus given in paragraph 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulation, 1988.
Group I	
Paper 1 : Accounting	Paper 1 : Advanced Accounting (Group I)
Paper 2A : Company Accounts 2B : Elements of Income Tax	Paper 5 : Income Tax and Central Sales Tax (Group II)
Paper 3 : Cost Accounting	Paper 4 : Cost Accounting (Group II)
Paper 4 : Auditing	Paper 2 : Auditing (Group I)
Group II	
Paper 5 : Mercantile Law, Company Law and Industrial Law	Paper 3 : Corporate and other Laws (Group I)
Paper 6 : Business Mathematics and Statistics	Nil
Paper 7 : Organisation and Management and Economics	Paper 6 : Organisation and Management and Fundamental of Electronic Data Processing (Group II)

(5) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination held under the Chartered Accountants Regulations, 1988 shall continue to be governed by the provisions of these Regulations till the commencement of Intermediate Examination to be held under paragraph 2A of Schedule 'B' to these regulations.

38. *Recruitments for passing the Final Examination*

(1) A candidate shall ordinarily be declared to have passed the Final examination if he passes in both the groups. He may appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination and in the remaining group at any subsequent examination.

(2) A candidate shall be declared to have passed in both the groups simultaneously if he secures at one sitting, a minimum of 40 per cent marks in each paper of both the groups and a minimum of 50 per cent marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a group if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of the group and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of that group.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Final examination held under the scheme of examinations prior to commencement of the examination under the syllabus given in paragraph 3A of schedule 'B' to these Regulations shall be entitled to the exemptions from appearing in the papers specified in the following tables and he shall be declared to have passed the Final examination if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each of the remaining papers and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all such remaining papers taken together.

Provided a candidate who is exempted from appearing in seven papers will be declared to have passed in the said examination if he secures a minimum of 50 marks in the remaining paper.

TABLE 'C'

Papers of the Final examination passed under Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1964	Exemption to which the candidate is entitled at any Final examination under the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988
Group I	
Paper 1 : Advanced Accounting	Paper 1 : Advanced Accounting (Group I)
Paper 2 : Advanced Accounting & Management Accounting	Paper 2 : Management Accounting and Financial Analysis (Group I)
Paper 3 : Costing	Paper 5 : Advanced Cost Accounting and Cost Systems (Group II)
Paper 4 : Auditing	Paper 3 : Advanced and Management Auditing (Group I)
Paper 5 : Taxation	Paper 7 : Direct Taxes (Group II)
Group II	
Paper 7 : Company Law	Paper 4 : Corporate Laws and Secretarial Practice (Group I)

TABLE 'D'

Papers of the Final examination passed under Schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations, 1964—prior to the 1st Jan., 1985 under three group system	Exemption to which the candidate is entitled at any Final examination under the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988
Group I	
Paper 1 : Advanced Accounting	Paper 1 : Advanced Accounting (Group I)
Paper 2 : Financial Management	Paper 2 : Management Accounting and Financial Analysis (Group I)
Paper 3 : Auditing	Paper 3 : Advanced and Management Auditing (Group I)
Group II	
Paper 4 : Company Law	Paper 4 : Corporate Laws and Secretarial Practices (Group I)
Paper 5 : Direct Tax Laws	Paper 7 : Direct Taxes (Group II)
Group III	
Paper 8 : Systems Analysis & Data Processing	Paper 6 : Systems Analysis, Data Processing & Quantitative Techniques (Group II)
Paper 9 : Cost Records & Cost Control	Paper 5 : Advanced Cost Accounting and Cost Systems (Group II)

TABLE 'E'

Papers of the Final examination passed under schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations 1964 or under the Regulations of 1988 (under two group system) prior to the commencement of the examination under the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' to these regulations.	Exemption to which the candidate is entitled at any Final Examination under the syllabus given in paragraph 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988.
Group I	
Paper 1 : Advanced Accounting	Paper 1 : Advanced Accounting (Group I)
Paper 2 : Management Accounting	Paper 2 : Management Accounting and Financial Analysis (Group I).
Paper 3 : Auditing	Paper 3 : Advanced and Management Auditing (Group I).
Paper 4 : Company Law	Paper 4 : Corporate Laws and Secretarial Practice (Group I).
Group II	
Paper 5 : Direct Tax Laws	Paper 7 : Direct Taxes (Group II)
Paper 6 : Management Information & Control Systems (Combination 'C') Paper 7 : Systems Analysis and Data Processing (Combination 'B')	Paper 6 : Systems Analysis, Data Processing and Quantitative Techniques (Group II).
Paper 8 : Secretarial Practice (Combination 'A')	Paper 4 : Corporate Laws and Secretarial Practice (Group I).
Paper 8 : Cost Systems and Cost Control (Combination 'B')	Paper 5 : Advanced Cost Accounting and Cost Systems (Group II).
Paper 8 : Management and Operational Audit (Combination 'C')	Paper 3 : Advanced and Management Auditing (Group I).

(5) A candidate who has passed in any one but not in both the groups in the Final examination held under the Chartered Accountants Regulations, 1988 shall continue to be governed by the provisions of those Regulations till the commencement of Final examination to be held under paragraph 3A of Schedule 'B' to these Regulations.";

V. in regulation 43(1) sub-regulation (6) shall be omitted; (ii) in sub-regulation (8) in the proviso, for the explanation, the following explanation shall be substituted, namely!:—

"*Explanation*

For the purpose of this sub-regulation, a member who sets up practice, with practice as his main occupation, after having been in employment for a minimum period of six years in one or more financial, commercial or industrial undertakings approved under Regulations 51 and 72 shall be deemed to have been in continuous practice for three years.";

VI. in regulation 45, in sub-regulation (1), for clause (b) the following clauses shall be substituted; namely;

(b) Such a person—

(i) is not less than 18 years of age on the date of commencement of articles;

(ii) has either passed the Foundation Examination or has been exempted from passing the Foundation Examination under these Regulations :

Provided that graduates who have passed the Entrance Examination shall continue to be eligible to register themselves as articled clerks.";

VII. in regulation 46, sub-regulation (5) shall be omitted

VIII. in regulation 51, for sub-regulation (2) the following shall be substituted :

"(2) The period of industrial training may range between nine months and twelve months during the last year of the prescribed period of practical training.";

IX. in regulation 57—

(i) sub-regulation (3) shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the words, brackets and figures "or sub-regulation (3)" and "in a case covered by sub-regulation (1) or sub-regulation (2)" shall be omitted;

X. for regulation 60, the following shall be substituted, namely :—

"60. *Working hours of an articled clerk*

Subject to such directions as may be issued by the Council, the working hours of an articled clerk shall be 35 hours per week to be regulated by the Principal from time to time."

XI. for regulation 64, the following shall be substituted, namely :—

"64. *Report to the Council* :—

(1) The Pricipal shall maintain a record about the progress of training imparted by him to the articled clerk, in such form and manner as may be determined by the Council from time to time.

(2) The Principal shall submit the records of training maintained as and when required by the Council. In the event of the death of the Principal his legal representative or the surviving partner shall submit the records, as and when required by the Council."

XII. in regulation 68, for sub-regulation (5) the following shall be substituted, namely :—

"(5) A member shall be entitled to engage a person as an audit clerk only if such person had been in service as a salaried employee for a minimum period of one year either under him or in the firm of chartered accountants in practice wherein he is a partner, on a monthly remuneration at the rates specified below, depending upon where the normal place of service of the audit clerk is situated :—

(a) cities with a population of one million and above—Rs. 750/- per month.

(b) cities/towns having a population of less than one million—Rs. 500/- per month.

"*Explanation*

For the purpose of this sub-regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India."

XIII. in regulation 69, in sub-regulation (1), for clause (b), the following clause shal be substituted, namely :—

"(b) Such a person—

(i) is not less than 18 years of age on the date of commencement of audit service;

(ii) has either passed the Foundation Examination or has been exempted from passing the Foundation Examination under these Regulations.

Provided that graduates who have passed the Entrance Examination shall continue to be eligible to register themselves as audit clerks.";

XIV. In regulation 69, for sub-regulation (5) shall be omitted;

XV. in regulation 72, sub-regulation (2) the following shall be substituted, namely :—

"(2) The period of industrial training may range between nine months and twelve months during the last year of the prescribed period of practical training.".

XVI. In Schedule 'A', after the existing Form "10", the following Form shall be inserted namely :—

"Form '10A'

(See Regulation 40)

Roll No.....

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Emblem)

Foundation Examination Certificate

This is to certify that ..... of ..... has passed the Foundation Examination held by the Institute of Chartered Accountants of India in the month of..... 19..... Given under the common seal of the Institute of Chartered Accountants of India, this ..... day of..... 19.....

(Seal)

Secretary."

XVII. In Schedule 'B'

(i) after paragraph 1, the following paragraph shall be inserted, namely :

"1A—*Papers and Syllabus for the Foundation Examination*

Paper 1—Fundamentals of Accounting

(One Paper—Three Hours—100 marks)

Level of Knowledge : Basic Knowledge.

Aim : To ensure acquisition of theoretical knowledge sufficient to provide a foundation for the professional examinations.

Detailed Contents

1. Accounting as a measurement discipline, Income measurement and related accounting concepts. Other accounting concepts. Relationship of accounting with economics and statistics. Role of an accountant in society.

2. Accounting process leading to the preparation of trial balance including rectification of errors, and preparation of final accounts (for non-corporate entities).

3. Depreciation accounting including methods thereof.

4. Inventory valuation.

5. Accouting for special transactions :
(a) Consignments;
(b) Joint Ventures;
(c) Average Due Date; and
(d) Bills of Exchange and Promissory Notes.

6. Self-Balancing Ledgers.

7. Simple problems in partnership accounts.

8. Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account and Balance Sheet including accounts of professional concerns.

Paper 2—Mercantile Law

(One Paper—Three Hours—100 marks)

Level of Knowledge : Basic Knowledge.

Aim : To ensure that the students have grasped the provisions of those branches of law with which they would be normally concerned in their professional work.

Detailed contents

1. The Indain Contract Act, 1872 including Indemnity and guarantee, Bailment and Pledge and Agency.

2. The Indian Partnership Act, 1932.

3. The Sale of Goods Act, 1930.

Paper 3—Mathematics and Statistics

(One Paper—Three Hours—100 marks)

Level of Knowledge : Basic Knowledge.

Aim : To ensure that the students have a basic understanding of important quantitative tools and their elementary application to business problems.

Detailed contents

(Section A—Mathematics..—50 Marks)

1. Number bases and binary arithmetic; conversion of a given base; Binary fractions.

2. Linear, Quadratic, Exponential and Logarithmic functions. Concept and determination of break even point.

3. Arithmetic and Geometric Progression including series.

4. Permutations and Combinations.

5. Matrices—means and operations, matrix inversion, solution to systems of linear equations by matrix inversion as well as pivotal reduction method.

6. Graph of Linear inequalities in two variables.

7. Calculus—

(a) Elements of trigonometry—to enable student to learn integral calculus with the aid of trigonometric ratios trigonometric ratios of angles associated with a given angle, addition formulae, multiple and submultiple angles, Transformation of a Sums into products and vice-versa, Definition of inverse circular function.

(b) Elements of differentiation, simple applications of differential co-efficients, maxima and minima of univariate functions; Rules of integration for indefinite and definite integrals. Simple application of integration to accounting and business problems.

(Section B—Statistics—50 Marks)

1. Classification and tabulation of data.

2. Measures of central tendency and dispersion.

3. Correlation and Regression (Linear and Bivariate only).

4. Probability and expected value.

5. Element of theoretical distribution—Binomial, Toisson, Normal.

6. Concept of standard error, interval estimation, determination of sample size, tests of hypotheses, analysis of variance.

7. Time series and forecasting.

8. Index Numbers.

9. Statistical decision theory—Pay-off and Regret Matrices. Decision making without probability and decision making with probability.

Paper 4—Economics

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of knowledge : Basic Knowledge.

Aim : (i) To provide basic knowledge of the framework of the economic theory to the extent it is useful for accountants; and

(ii) To ensure that the students are aware of the economic development of the country leading to the contemporary state in which the economy is placed.

Detailed Contents :

Micro Economics.

1. Nature and scope of Economics, Economic Models and their uses.

2. Demand and Supply Laws of Demand and Supply, Elasticity of Demand and Supply, Factors affecting Demand and Supply, Demand forecasting.

3. Meaning of Production, Factors of Production, Scale of Production, Law of Returns, Major components of costs.

4. Meaning of a Market, Types of Markets, Theory of price and output determination in different market structures and in different economic systems.

Indian Micro Economic Environment.

1. Economic Growth in India—Population and Economic Growth.

2. General profile of agriculture and industry in India : Interdependence of industry and agriculture for economic advancement in India.

3. Industrial Policy of Government, Industrial Growth in India—Problems and prospects.

4. National income in India—Theory and Application.

5. Fiscal Policy in India.

6. Indian Monetary Policy—The functions of commercial banks and Reserve Bank of India.

7. Indian International trade—Exports and Imports—Balance of Trade and Payments."

(ii) after paragraph 2, the following paragraph should be inserted, namely :—

"2A. *Papers and Syllabus for the Intermediate Examination.*

GROUP I

Paper 1—Advanced Accounting

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : To test the ability of the students to prepare accounting records and final accounts in order to reflect the economic transactions and financial affairs of business and other organisations in accordance with current legal requirements and professional standards.

Detailed Contents :

1. Departmental Accounts and Branch Accounts (including Foreign Branches); Royalty, Hire Purchase and Instalment Sale Transactions; Investment Accounts; Packages and Empties; Goods on Sale or Return, Voyage Accounts; Contract Accounts; Computation of Insurance Claims for Loss of Stock and Loss of Profit.

2. Accounts for Agricultural Farms.

3. Higher level problems on Partnership Accounts (including dissolution and conversion into company).

4. Company Accounts—Issue of shares and debentures and redemption of shares and debentures; Preparation of Final Accounts of Companies.

5. Preparation of Final Accounts of Banking, Insurance and Electricity Companies.

6. Simple problems of amalgamation, absorption and reconstruction.

7. Statement of Affairs (including deficiency/surplus Accounts) and Liquidator's Statement of Account of the winding up.

8. Preparation of accounts from incomplete records (single entry.)

9. Simple ratio analysis.

10. Introduction to the system of government accounting.

Paper 2—Auditing

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Working knowledge.

Aim : To test the understanding of the students regarding the techniques and procedures of auditing as also their ability to apply the same to normal practical situations.

Detailed contents

1. Auditing—nature and scope, audit process, objectives of audit, basic principles governing an audit. Types of audits, Relationship of auditing with other subjects, Internal Audit and External Audit.

2. Conduct of audit—audit programmes—working papers—audit not books—audit files—permanent audit files.

3. Audit evidence—physical verification, documentation, scanning, direct confirmation, recomputation, obtaining certificates.

4. Evaluation of Internal Control System—need and its impact on detailed checking.

5. Test Checking—Techniques of test checks—elements of statistical sampling.

6. Audit of payments—general considerations—wages—capital expenditure—other payments and expenses—petty cash payments; Audit of payments into and out of the bank—reconciliation of the bank statements with the cash book.

7. Audit of receipts—general considerations—cash sales—receipts from debtors—other receipts.

8. Audit of purchases—vouching cash and credit purchases—forward purchases—purchases returns.

9. Audit of sales—cash and credit sales—goods on consignment—sale on approval basis—sale under hire-purchase agreement—returnable containers—various types of allowances given to customers—sales returns—sales ledger.

10. Audit of suppliers' ledger and the debtors' ledger—self-balancing and the sectional balancing system—total or control accounts—loose leaf and card ledgers—confirmatory statements from credit customers and suppliers—provision for bad and doubtful debts.

11. Audit of impersonal ledger—capital expenditure, deferred revenue expenditure and revenue expenditure outstanding expenses and income—repairs and renewals—distinction between reserves and provisions—implecations of charge in the basis of accounting.

12. Valuation and verification of assets—general principles —fixed assets, wasting assets, current assets including verification of cash-in-hand and at bank, investments, inventeries, freehold and lease-hold property, loans, bills receivable, sundry debtors, plant and machinery, patents.

13. Verification of Liabilities.

14. Audit of Incomplete records.

15. Special points in audit of different types of undertakings i.e. Educational Institutions, Hotels, Clubs, Hospitals, Hire-purchase and Leasing Companies etc. (excluding banks, electricity companies, co-operative societies and insurance companies).

16. Audit of limited companies—appointment of auditors, removal of auditors, the powers and duties of auditors, the auditor's report, audit of share capital, transfer of shares.

17. Features of Government Audit—Comptroller and Auditor General and his constitutional role : Basic principles of Government auditing.

18. Auditing in EDP Environment—basic consideration.

Paper 3—Corporate and Other Laws

(One Paper—Three Hourse—100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : To test the general comprehension of the provisions of certain corporate and other laws and their applications to practical situations.

Detailed Contents :

1. The Companies Act, 1956 : Sections 1 to 145.

2. The Negotiable Instruments Act, 1881.

3. The Payment of Bonus Act, 1965. Basic awareness of the following Acts.

4. The Payment of Gratuity Act, 1972.

5. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

6. The Societies Registration Act, 1860.

7. The Co-operative Societies Act, 1912

GROUP II

Paper 4—Cost Accounting

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : To assess the understanding of costing concepts and the application of the methods and techniques of cost accounting.

Detailed Contents

1. Objectives, importance and advantages of Cost Accounting, Cost concepts, Types of costing, Installation of a costing system, Essential of a good cost according system, Difference between Cost Accounting and Financial Accounting Elements of cost, cost unit and cost centre.

2. Materials :

(a) Materials purchase procedure, receiving and inspection.

(b) Materials control, objectives of materials control, classification and codification of materials, Inventory control methods-fixation of stock levels maximum level, minimum level, re-order quantity, re-order level ABC analysis, two bin system, perpetual inventory system, physical verification of inventory.

(c) Material issue procedure, bill of material, return of material, transfer of material.

(d) Stores records—bin cards, stores ledger, pricing of material issues including materials returned to vendors and stores.

(e) Accounting for wastages, scrap, spoilages, defectives and obsolete materials.

(f) Accounting for control over tools, patterns, designs, blue prints, dies and other similar assets of short-term value.

3. Labour :

(a) Labour cost control, its importance, time-keeping, time booking and their objectives, methods of time keeping and time booking. Time and motion study.

Control of idle time, over-time and their treatment in cost accounting, Labour turnover, its causes, methods of measuring, effects of labour turnover, how to minimise labour turnover, cost of labour turnover treatment of the cost of labour turnover.

(b) Systems of wage payment including bonus and incentive schemes, job evaluation, merit rating, methods of job evaluation.

4. Overheads :

(a) Accounting and control of manufacturing overhead, classification of overhead, grouping and codification, collection and departmentalisation of manufacturing overhead. re-apportionment, overhead absorption methods. treatment of under or over absorption of overhead.

(b) Accounting and control of administrative, selling and distribution overheads.

(c) Treatment of certain items in costing, e.g., depreciation, interest on capital, research and development expenses, packing expenses, fringe benefits, etc.

5. Methods of Costing, Viz ,

(i) Job Costing

(ii) Contract Costing

(iii) Batch Costing

(iv) Process Costing—Joint products and by-products

(v) Unit Costing

(vi) Operation Costing and Operating Costing.

6. (a) Preparation and presentation of cost data and information particularly tabulation of cost data, preparation of cost sheets and cost statements. General introduction to Cost Accounting Records and Rules (industry-wise details are not expected).

(b) Cost control accounts. Non-integrated accounts. Reconciliation of cost and financial accounts, Integrated system of cost and financial accounts.

7. Marginal costing, methods of segregating semi-variable costs into fixed and variable components. Concepts of Break-Even analysis; Standard Costing and Variance Analysis (elementary problems). Budgetary Control (elementary problems).

8. Uniform costing and inter-firm comparison.

Paper 5—Income Tax and Central Sales Tax

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : (a) To test the understanding of the students regarding the basic principles underlying the substantive provisions of Income-tax Law and their application in solving simple problems on computation of income of an individual under various heads of income.

(b) To test whether the students have acquired a working knowledge of the basic principles of Central Sales Tax Act.

SECTION 'A'—Income-Tax (75 Marks)

Detailed Contents :

Certain important definitions in the Income-tax Act, 1961, such as Agricultural Income, Assessee, Assessment Year, Capital Asset, Company, Indian Company in which public

are substantially interested, Charitable Purpose, Dividend. Income, Person, Short-term Capital Asset, Transfer.

— Concept of previous year.

— Basis of charge, Residential status and scope of total income.

— Income deemed to be received/deemed to accrue or arise in India.

— Incomes which do not form part of total income.

— Heads of income and the provisions governing computation of income under different heads.

— Income of other persons included in assessee's total income.

— Aggregation of income and set-off or carry forward of losses.

— Deductions from gross total income.

— Income-tax Authorities, Appointment, Control, Jurisdiction, Powers.

— Procedure for assessment, appeals and revisions. Students will be expected to tackle simple problems concerning assessees with status of individual covering the above areas.

SECTION 'B'—Central Sales Tax (25 Marks)

The Central Sales Tax Act, 1956.

Paper-6—Organisation & Management and Fundamentals of Electronic Data Processing.

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

SECTION 'A'—Organisation & Management (50 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aim : To ensure that the students have grasped various concepts and functions of organisation and management relevant to a professional accountant.

Detailed Contents :

1. Introduction :

Basic concepts of Organisation and Management—Nature and types of Organisations—Basic elements of Organisations and their role in economy and society.

Management—Historical development—Theoretical perspectives of Management. Elements, processes and functions of management—Environmental influences on Organisation and Management—Organisational Objectives—Social responsibilities of Management.

2. Planning and decision making :

Basic concepts and principles of planning and decision making—Their relationship to other managerial functions. Elements, techniques and processes—Types of plans and decisions—Implementation of plans and decisions

3. Organising and Staffing :

Basic concepts of organising and staffing—Structural design of organisation and its importance, Departmentalisation, span of control, delegation, centralisation line-staff, etc.—Traditional and modern organisational structures—Principles of organising and staffing—Application to accounting and finance functions.

4. Directing and leading :

Basic concept and techniques. Communication, motivation and leadership—Processes and approaches—The concept, principles and applications of organisational behaviour.

5 Control and Coordination

Basic concepts, elements, processes and techniques of control and co-ordination.

Section 'B'—Fundamentals of Electronic Data Processing—(50 Marks)

Level of Knowledge : Basic knowledge.

Aim : To ensure understanding and appreciation of abroad nature and fundamentals of Electronic Data Processing.

Detailed Contents :

1. Elements of Data Processing—data, information, input, processing and output. Data Concepts—fields, records, files, file structure.

2. Computers and their characteristics, brief history of computers, computer hardware, basic operations of a computer, categories of commercial computers—main frames, mini-cumputers, micro computers.

3. Input devices—magnetic tape, magnetic desk, floppy disk, MICR, OCR, VDU, etc.

Output devices-printers, VDU, computer out-put microfilming. Terminals and data communications, Networks, Distributed Systems.

Software—Systems software, application software, specification software.

Electronic spread sheet, Word-processing, Data base management systems.

Data representation—Binary, BCD, Octal, Hexadecimal, EBCDIC and ASCII.

Types of computer memory—core, semic-conductor, RAM ROM, Bubble. Concepts relating to memory addressing.

4. Computer processing techniques—batch processing, online processing, off-line processing, multi-programming, time sharing, real time processing. Data base Features of distributed versus centralised data base. Recent advances in computer technology relating to commercial computers.

5. Introduction to flow charts : systems flow charts, run flow charts, program flow charts—illustrations, benefits and limitations. Decision tables—types, illustrations, benefits and limitations.

6. Introduction to computer programming : hierarchy of computer languages, simple program writing using COBOL and BASIC languages."

(iii) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely :

3A :—Papers and Syllabus for the Final Examination

GROUP I

Paper 1—Advanced Accounting

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge

Aim : To test the understanding of the students regarding the professional standards, principles and procedures of accounting principles and procedures of accounting as well as their ability to apply the same to different practical situations.

Detailed contents :

1. Advanced problems of Company Accounts.

2. Higher problems of amalgamation, absorption and reconstruction.

3. Valuation of business and shares.

4 Consolidated accounts of Holding Companies.

5. Accounting Standards, Statements and Guidance Notes on various accounting aspects issued by the Institute and applications thereof with particular reference to the above topics.

6. Developments in accounting—Inflation adjusted accounts, Human Resources Accounting, Social Accounting and Value Added Statements.

7. Limitations of Financial Statements.

Interpretation and analysis of financial statements including interpretation and analysis of financial data, Ratio analysis, Counter-check by two different ratios analysis, Counter-check by two different ratios, limitations of ratios. Comparative statement analysis and Inter-firm comparisons.

8. Cash flow, statement of source and application of funds.

9. Special features of accounting for non-profit making organisations and public utilities.

Paper 2 Management Accounting and Financial Analysis

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge.

Aim : To assess whether the students have acquired a sound knowledge of the concepts and techniques of management accounting and related managerial decision making of organisations including Public Sector Undertakings.

Detailed Contents :

1. Meaning, Importance and Objectives of Financial Management Functions of a Finance Manager.

2. Short-term and Long-term Financial Planning and Forecasting; Predicting the incipient industrial sickness; Operating and Financial Leverage; Cost-Volume-Profit Analysis.

3. Management of Working Capital—Cash Management, Receivables Management, Inventory Management and Financing or Working Capital.

4. Sources of long-term and short-term finance; control on Capital issues including Bonus Shares; Capital Structure; Dividend Policy; Lease Financing; Issue of shares and securities; Listing of securities.

5. Capital Budgeting—Preparation of Project Report, Financial Projections, Techniques for Evaluation of Capital Projects like Payback Method, Rate of Return, Discounted Cash Flow—Net Present Value and Internal Rate of Return Methods; Capital Rationing; Risk Analysis in Capital Budgeting and Evaluation of Risky Investments; Social Cost Benefit Analysis; Network Techniques for Control of Capital Budgeting—PERT and CPM.

6. Cost of Capital—Cost of different Sources of Finance, Weighted Average Cost of Capital, Marginal Cost of Capital.

7. Budget & Budgetary control—Financial Budgets (Including Responsibility Budgets) leading to preparation of Master Budget; Fixed and Flexible budgeting, Performance budgeting, Zero-Base budgeting; Reporting for performance at different levels.

8. Negotiating Term Loans with Banks and Financial Institutions, Appraisal of Term Loans by Financial Institutions in India.

9. Management of Investment Portfolio, Selection of securities, Timing of buying and selling decisions.

10. Special features of financial management in public sector undertakings.

11. Inflation and financial management.

12. Corporate taxation and its impact on corporate financing.

13. Introduction to International Financial Management—Raising international finance and exchange rate, Risk management, foreign exchange transactions.

Paper 3—Advanced and Management Auditing

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge.

Aim : To assess whether the students have acquired a sound knowledge of current auditing practices and procedures and can apply them to divorse practical situations.

Detailed Contents :

1. Planning and Programming of Audit

Planning the flow of audit work-interim audit, continuous audit. Division of work between different levels of assistants problems of supervision—review of audit notes and working papers—principal's ultimate responsibility—question of delegation. Control over the quality of audit work. Reliance on another auditor, on internal auditor, on an expert.

2. Internal Control and Internal Audit

Evaluation of Internal Control procedures—Techniques including questionnaire, flow-chart. Internal Audit and External Audit—Coordination between the two.

3. Special Audit Techniques

Selective verification—statistical sampling. Special audit procedures—witnessing physical verification of assets—direct circularisation of debtors and creditors.

Review of accounts on an overall basis—Balance Sheet Audit—Ratio Analysis etc. Improving the efficiency of auditing—systems auditing and risk based auditing.

4. Audit of Limited Companies;

(a) Auditor's responsibility vis-a-vis

(i) Statutory requirements under the Companies Act.

(ii) Audit of branches.

(iii) Joint audits.

(b) Concepts of true and fair and materiality in the context of audit of companies.

(c) Significance of obtaining information and explanation from the management—degree of reliance to be placed thereon.

(d) Audit reports—Qualifications—Notes on accounts. Distinction between notes and qualifications. Detailed observations by the statutory auditor to the management vis-a-vis obligations of reporting to the members. Special reports for prospectus.

(e) Dividends and divisible profits—financial, legal and policy considerations with special reference to depreciation.

5. Special points in audits of public sector companies-Directions of Comptroller and Auditor General under Section 619 - concepts of propriety and efficiency audit .

6 Special Audit.

7. Cost Audit

8. Certification :

Certificates under the Payment of Bonus Act, import/export control authorities, etc., - Distinction between certificates and reports. Specific services to non-audit clients.

9. Investigations :

Investigations such as concerning schemes of amalgamation, reconstruction, purchase or sale of business etc.

10. Audit under different provisions of the Income Tax Act.

11. Special features of audit of banks, insurance companies and co-operative societies.

12. Statements/Standards and Guidance Notes :

Accounting Standards, Statements on Auditing Practices and guidance notes issued by the Institute connected with accounting and auditing matters - concept of generally accepted auditing practices - audit with reference to such practices - its significance.

13. Rights, duties and liabilities of auditors - third party liability - nature and extent.

14. Professional ethics and code of conduct.

15. Concept of Management and Operational Audit - its nature and purpose, organisation - Audit Programme - Behavioural problems.

16. Specific areas of Management and Operational Audit involving review of internal control purchasing operations, manufacturing operations, selling and distribution, personnel policies, systems and procedures.

17. Special audit assignments like audit of bank borrowers, audit of stock exchange brokers.

18. Computer auditing - specific problems of EDP Audit, need for review of internal control especially procedure controls and facility controls; techniques of audit of EDP output. Use of the computer for internal and management audit purposes - Test packs, computerised audit programmes. Involvement of the auditor at the time of setting up the computer system.

Paper 4 - Corporate Laws & Secretarial Practice

(One Paper - Three Hours - 100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge

Aim : To test the students' knowledge of the law and practice in respect of Company Law and related Acts.

Detailed Contents :

1. The Companies Act, 1956 (Section 146 onwards till end).

2. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

3. The Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

4. The Capital Issues (Control) Act, 1947, and Exemption Order issued thereunder.

5. The Sick industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

6. Rules of Interpretation of Statutes, Deeds and Documents.

7. Application of Secretarial Procedure and Practices.

GROUP II

Paper 5 - Advanced Cost Accounting and Cost Systems, (One paper - Three Hours - 100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge

Aim : To test the understanding of the students regarding the principles and procedures of cost accounting as well as their ability to apply the same to different practical situations for managerial decision making.

Detailed Contents :

1. Cost Classification and Analysis.

2. Cost Concepts in decision making - Relevant Cost, Differential Cost, Incremental Cost and Opportunity Cost.

3. Marginal Costing - Distinction between marginal costing and absorption costing. Break-even Analysis, Cost-Volume-Profit Analysis; Break-even charts, Contribution margin and various decision making problems like Make or Buy, Shut down or Continue, Expand or Contract, Pricing Decisions in special circumstances, Product Decisions.

4. Problems on decision making such as Retain or Replace, Repair or Renovate. Now or later, Change vs. Status quo, Sell or Further Process, Own or Lease, Sell or Scrap or Retain, Pricing decisions, Product decisions, Marketing and Distribution decisions. Inventory control, Plant location, Product development, Competitive pricing, Price differentials and discounts and Pricing/Marketing strategies.

5. Cost Control as distinct from Cost determination, Control over wastages, scrap, spoilage and defectives.

6. Management Control-Responsibility Accounting cost profit and investment centres, problems on transfer pricing using the contribution approach.

7. Standard Costing and Various Analysis - Material, Labour and Overheads; Reporting of Variances.

8. Cost Reduction-Techniques of cost reduction such as Work Study, Time and Motion Study and Value Analysis; Employee Participation in Cost Reduction Programmes; Significance of Constituting Special Cost Reduction Cells.

Paper 6 - Systems Analysis, Data Processing & Quantitative Techniques.

(One Paper - Three Hours - 100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge

Aim : (i) to test the ability of the students to apply techniques of systems analysis and design to design and implement business computer applications.

(ii) To test the ability of the student to apply quantitative techniques to business problems.

Detailed Contents :

1. Basic requirements of MIS - its need, purpose and significance; recognising the need to provide different types of information at different levels of management. Systems approach to management problem solving. Need to instal information systems specially designed to meet the objectives of each business; conceptual knowledge on usage of information for decision making.

2. Systems development process.

3. Concepts of systems analysis and design, programming methods, techniques and tools.

4. Change-over from manual to computerised system-related problems and evaluations.

5. Design of computerised commercial applications : financial accounting, inventory control, production control, share accounting, payroll preparation and accounting, sales accounting, invoicing.

6. Computer management-organisation and staffing of the EDP Department.

7. Selection and installation of computer-selection of computer, criteria for selection, evaluation of tenders, financial matters (rent, lease, buy, installation costs), Computer Bureaus.

8. Controls in EDP set up.

9. Standards-management, methods and procedure standards.

10. Security of computer installation, stand-by facilities, Hazards, to be guarded forefire, fire detection and extinguishing equipment, action to be taken in the event of fire, how to save the data in such cases . Insurance cover.

11. Quantitative techniques; Linear programming, Transportation, Assignment problems, PERT/CPM.

Statistical decision theory-EVPI, Posterior analysis using Binomial and Normal functions, Queuing Theory-Single Channel: Simulation.

Paper 7—Direct Taxes

(One Paper—Three Hours—100 Marks)

Level of Knowledge : Expert Knowledge

Aim : (i) To test whether the students have achieved a thorough knowledge of the Income-tax Act, 1961, Wealth Tax Act, 1957, Gift Tax Act, 1958 and the relevants rules and principles emerging from leading cases.

(ii) To test whether the students have ability to apply their knowledge of the provisions of law to various situations in actual practice with particular reference to areas where tax planning could be undertaken.

Detailed Contents.

I. Income Tax Act, 1961.

II. Wealth Tax Act, 1957.

III. Gift Tax Act, 1958.

While covering the Direct Tax Acts, students should familiarise themselves with considerations relevant to tax planning. These may include tax considerations with regard to specific management decisions, foreign collaboration agreements, amalgamations, tax incentives, personnel compensation plans, accounting and other precautions to be observed to maximise tax reliefs etc.

Paper 8 - Indirect Taxes

(One Paper - Three Hours - 100 Marks)

Level of Knowledge : Working Knowledge.

Aims : To test whether the students have acquired a working knowledge of the basic principles of hte laws governing Central Excise and Customs.

Detailed Contents :

I. Central Excise and Salt Act, 1944 as amended up-to-date. Central Excise Tariff Act, 1985 as amended up-to-date.

The customs and Excise Revenue Appellate Tribunal Act, 1986.

1. Nature of Excise Duty, Legislative history, coverage etc. Levy and collection of Excise duties under the Central Excises and Salt Act, 1944, Legal effects of Notifications, Tariff advices, trade notices.

2. Provisions governing manufacture and removal of excisable goods;

Valuation under the Central Excise and Salt Act, 1944, Central Excise (Valuation) Rules, 1975, filing, and approval of price lists.

3. Classification of goods under Central Excise Tariff Act, 1985 with reference to Rules of Interpretation, filing and approval of classification list.

4. Assesment including provisional assesment, self-removal procedure, payment of duty and rate of duty Record based control and Production based control.

5. Short levy, non-levy, erroneous grant of refund, duty paid in excess. Refunds and powers of Central Government regarding short levy and non-levy.

6. Licensing procedures, formalities and related bonds.

7. Procedure relating to storage of excisable goods, time and manner of payment of duty, rules relating to marketing of goods, gate passes and other matters relating to removal of goods.

8. Maintenance of records, registers and filing of returns.

9. Entry/retention of duty paid goods in the factory.

10. Remission of duty on goods used for special industrial purposes.

11. Procedure for exports, duty drawback.

12. Proforma credit and MODVAT.

13. Departmental organisation set-up. Adjudication and Appellate procedures-Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and the Customs and Excise Revenue Appellate Tribunal.

14. Offences and penalities.

15. Exemptions for small scale industries.

II. Customs Act, 1952 and Customs Tariff Act, 1975.

1. Principles governing levy of and exemption from customs duties.

2. Basic principles of classification of goods and valuation of goods.

3. Customs authorities, appointment of customs ports, ware-housing stations etc.

4. Provisions governing importation and exportation of goods, Special provisions ragarding baggage, goods imported or exported by post, and stores.

5. Detailed procedure in relation to transportation and ware-housing.

6. Drawback of customs duties paid.

A. K. MAJUMDAR
Secretary

Foot note :

1. The Chartered Accountants Regulations, 1988 were buplished in the Gazette of India, Extra-ordinary dated 1-6-1988 vide Institute's Notification No. 1-CA(7)/134/88 dated 1-6-1988.

2. The details of subsequent amendments published in the Gazette of India are as under :—

1. Amendment in Regulation 48, published in the Gazette of India dated 7th October, 1989 vide Notification No. 1-CA(7)/1/89 dated 25th September, 1989.

2. Amendment in Regulation 159 - published in the Gazette of India dated 19th January, 1991 vide Notification No. 1-CA(7)/10/90 dated 2nd January, 1991.

3. Amendment in Regulations 6, 35, and 39 - published in the Gazette of India dated 19th January, 1991, vide Notification No. 1-CA(7)/11/90 dated 4th January, 1991.

4. Amendment in Regulation 190 - published in the Gazette of India dated 2nd February, 1991 vide Notification No. 1-CA(7)13/90 dated 14th January, 1991.

5. Amendment in Regulation 87, 87, 92, 97, 111, 112 and 157 - published in the Gazette of India dated 2nd March, 1991 vide Notification No. 1-CA(7)/12/91 dated 12th February, 1991.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 14th February 1992

No. V-33(13)-17/86-Estt.IV.—The existing entry at Sl. No. 6 of Employees' State Insurance Corporation Notification of even number dated 3-10-1991 regarding reconstitution of the Regional Board, West Bengal may be read as :—

6. Shri A. B. Chaudhuri, Employer's representatives

Labour Adviser,

Indian Chamber of Commerce,
4, India Exchange Place,

CALCUTTA-700001.

SMT. KUSUM PRASAD
Director General

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 17th February 1992

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/495.—WHEREAS THE employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule I against their names.

SCHEDULE I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F. C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. The Ahmedabad Manufacturing Calico Printing Company Limited, (Calico Mills) Outside Jamalpur Gate, Ahmedabad.	GJ/279	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2927. dated 18-3-90	17-9-91	18-9-91 to 17-9-94	2/644/82/DLI
2.	M/s. Gujarat Machinery Manufacturers Limited, P.B. No. 1, Karamsad-388325 (Gujarat)	GJ/4499	S-35014/280/83-PF-II(SS-II) dated 2-6-86	23-12-89	24-12-89 to 23-12-92	2/961/83-DLI.
3.	M/s. Tapti Industrial Engineers, Mankush Compound, A.K. Road, Surat-395008.	GJ/16714	2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3914 dated 1-8-1990	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2761/90-DLI.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/DI I/Exemp/89/Pt.I/503.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Coimbatore from the operation of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. P.S.G. Industrial Institute, Peelamedu Coimbatore-641004.	TN/88	1-12-88 to 30-6-90	2/3966/92-DLI
2.	M/s. Orient Textile Industries IMMC Campus East Main Road, Mettur Dam-636401 (Selem Dt.)	TN/17088	1-1-90 to 28-2-90	2/3965/92-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilty for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt I/511.— WHEREAS M/s. Chowgale Matrix Hobs Ltd. Regd. Office and Works, 26/A, Industrial Estate, Patancheru-502319, Distt. Medak, Andhra Pradesh (Code No AP/5726), have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):—

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation

of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1128 dated 19-12-89 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 1-3-92 to 28-2-95 upto and inclusive of the 28-2-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made be the employer in payment of premium the responsibilty for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/ payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/519.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

Now, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against said Scheme has been granted by the R.P.F.C. West Bengal from the operation of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE—I

Region : West Bengal

Sr. No.	Name & Address of the establbishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Jay Shree Chemicals Ltd., 14, Netaji Subash Road, Calcutta-700 001.	WB/13356	1-5-90 to 30-4-93	2/3923/91-DLI
2.	M/s. Engineering Export Promotion Council, World Trade Centre (3rd Floor) 14/1B Ezra Street, Calcutta-700001. (Including their Territorial Division 2 —One each at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras, Sub Regional Offices at Ahmedabad, Bangalore and Jallandhar, and foreign offices at coted' Invoire, U.S.A., U.A.E Immermannstr, Great Britain, Los Angles, Kenya, Australia).	WB/15617	1-3-90 to 28-2-93	2/3922/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if——on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

7—489 GI/91

The 18th February 1992

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./527.—WHEREAS M/s. Dominant Offset (Pvt.) Ltd., Palam, Gurgaon Road, Gurgaon (Code No. HR/10633) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-5-91 to 30-4-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ———— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall

before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. I/535.—WHEREAS M/s. Modern Food Industries India Ltd., Old Exhibition Ground, Taratala Road Calcutta 700088 (Code No. WB/15281), have applied for exemption under sub Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/104/87/PF. II dated 3-4-86 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 16-10-88 to 15-10-91 upto and inclusive of the 16-10-91.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, gave a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./543.—WHEREAS M/s. Punjab Ceramics Ltd. P.B. No. 36, Dabwali Road, 151001 (Punjab Bathinda (Code No. PN/10557) have applied for exemption under sub. Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-90 to 28-2-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commisioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

The 19th February 1992

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/551.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions pecified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 Years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted / extended	Date of earlier exemption was	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Escorts Tractors Limited, Scindia House, Connaught Circus, New Delhi-110001.	DL/2676	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/ dated 20-10-89	30-11-90	1-12-90 to 30-11-93	2/1086/89-DLI
2.	M/s. K L. Rathi Steels Limited, Loni Road, Shahdara, Delhi-32	DL/3365	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/ dated 20-10-89.	7-11-91	8-11-91 to 7-11-94	2/607/81-DLI
3.	M/s. Sachdeva Pvt. Ltd., 69/1 A, Najafgarh Road, New Delhi-110015.	DL/3684	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 28-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2095/89-DLI
4.	M/s. Sachdeva Textiles Pvt. Ltd., 69/1A, Najafgarh Road, New Delhi-110015.	DL/6617	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/ dated 18-11-89.	31-7-90	1-8-90 to 31-7-93	2/328/90-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commisioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group, Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/559.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for extemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Karnataka Silk Industries Corporation Limited, Unit Sunsilk Mills, Channapatna-571501.	KN/47	S-35014/220/86/SS-II dated 20-8-86	19-8-89	20-8-89 to 19-8-92	2/1471/86-DLI
2.	M/s. Sujata Textiles Mills, P.O. Nanjangud, Karnataka-571301.	KN/89	S-35014/285/85/SS-IV dated 25-11-85	24-11-88	25-11-88 to 24-11-91	2/763/82-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, th exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/567.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's. Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Hi-Power Automotive Parts P. Limited, D-30, Industrial Estate Ambattur, Madras-58.	TN/10788	2/1959/DLI/Exemp/89/6103 Pt. I/6103, dated 10-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2816/90-DLI
2.	M/s. Sundaram Finance Limited, 21, Patulles Road, Madras-2 (including all branches under the said Code No.)	TN/10595	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 10-7-91	19-11-91	20-11-91 to 19-11-94	2/1308/85-DLI
3.	M/s. Southern Swichgear Limited P.B. No. 114, Avadi Road, Ambattur, Madras-600058.	TN/3469	S-35014 (73) 82 PF-II SS-II dated 2-9-86	29-10-88	30-10-88 to 29-10-91	2/503/81-DLI
4.	M/s. K.H' Shoes Limited (B' Unit), Bye Pass Road, Ranipet-632401, North Arcot District.	TN/19687	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 18-9-89	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94	2/2040/89-DLI
5.	M/s. Carborundum Universal Limited, 28, Raja-ji Road, Madras-600001.	TN/860	S-35014/171/85-SS-IV dated 28-6-85	27-6-88	28-6-88 to 27-6-91	2/1246/85-DLI
6.	M/s. Ponds (India) Limited, 26-C-IN-C Road, Madras-600105.	TN/5394	S-35014/418/82 PF-II/SS-II dated 9-4-87	31-12-88	1-1-89 to 31-12-91	2/286/79-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case, within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/575.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applid for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule I against their names.

SCHEDULE I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt.'s Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry of earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Standard Packagings, 6-6, Assisted Pvt. Industrial Estate, Nellore-524004.	AP/6980	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/602 dated 15-9-89	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/1997/DLI/89
2.	M/s. Shanti Marketing & Service (P) Ltd., 7-1-25, Greenlands, Ameerpet, Hyderabad-500016, (A.P.)	AP/16950	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/1616 dated 13-9-91	31-1-92	1-2-92 to 31-1-95	2/3801/91/DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case, within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay-400005, the 14th February 1992

No. UT/DBD&M/499A/SPD 172/91-92.—The Provisions of the Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Master Plus) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 15th November 1991 are published here below.

MASTERSHARE PLUS UNIT SCHEME—1991

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963) the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme :

I. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

This scheme shall be called the Mastershare Plus Unit Scheme—1991 and shall come into force on December 9, 1991.

II. DEFINITIONS :

In this Scheme unless the context otherwise requires :—

(a) The 'Act' means the Unit Trust of India Act, 1963.

(b) 'Applicant' means a person having application for the units under the scheme.

(c) 'Application' means the form of application prescribed for offer of units for all applicants and containing the terms and conditions for the purpose of unit subsription to the scheme for the investing public.

(d) 'Allotment' means allotment of units against a valid application in a manner determined by the Trust for the purpose.

(e) 'Issue' means the total number of units offered and issued under the scheme for subscription under relevant application form as stated in (c) above.

(f) 'Listed' means the listing of units for the purpose of trading in a recognised Stock Exchange which is for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(g) 'Mastershare Plus' means Units as hereinafter defined and the share or unit in the capital of 'Master Share Plus Unit Scheme' or 'Master Plus' as hereinafter defined.

(h) 'Mastershare Plus Unit Scheme' or 'Master Plus' means units issued under Mastershare Plus Unit Scheme—1991.

(i) Number of units in issue' means the aggregate on the number of units sold and outstanding after the issue is closed.

(j) 'Offer of Units' means the full offer for sale of units made by the Trust under offer documents to investors to constitute the capital of the under the Scheme.

(k) 'Person holding units or unitholder' means a person who holds units for the time being.

(l) 'Registrar' means a person appointed to act as the Registrar from time to time under the scheme.

(m) 'Regulations' means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(n) 'Trading' means the dealing in by buying or selling units through any of the Stock Exchange after the first allotment of units.

(o) 'Unit' means one undivided share of the face value of Rupees Ten.

(p) 'Unit Capital' means the aggregate of the face value of units issued and allotted under the Scheme.

(q) Words not defined in this Scheme shall have the meanings assigned to them under the Act.

(f) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the femine and vice versa.

III. PRINCIPAL OBJECTIVE

This Scheme is made with a view to providing an opportunity for common investors to participate a share growth of the corporate securities and market. Long term capital appreciation would be the major goal of the scheme and the emphasis will therefore be on sharing of growth through rights and bonuses rather than through distribution of income by way of dividends.

IV CATEGORIES OF INVESTORS

Application for units may be made by the following classes of persons :—

1. An individual of individuals not exceeding 3 (three). None of them is a minor.

2. MINOR

On behalf of MINOR, father, mother or the lawful guardian shall be eligible to make the investment.

3. A Body Corporate shall mean and include the Company registered under the Companies Act, 1956, and a Societies Registration Act, 1860 or established under State or Central Law for the time being in force. Such Society being hereinafter referred to as "the Society".

4. Eligible Trust shall have the meaning assigned to it under clause (aaa) of Regulation 2.

5. Society shall mean and include as specified in the definition of the Body Corporate as above.

6. Partnership Firm

A partnership firm shall have the meaning respectively assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 but the expression partner shall also include any person who being a minor has been admitted to the benefits of partnership firm.

IV SALE OF UNITS

(a) Units under this Scheme are offered to and open for subscription only by resident individuals, Companies/bodies corporate established in India.

(b) An individual or individuals not exceeding two number who are adults (on joint or either or survivor basis) may be permitted to apply for units.

(c) A parent, step parent or other lawful guardian may make an application on behalf of a minor.

(d) Applications shall only be made in the form prescribed in multiples of hundred with a minimum of hundred units of the face value of Rs. 10/- each.

(e) Duly completed forms of application accompanied by the payment for the units applied for shall be tendered at any of the offices of the Trust or at any authorised Collection Centre during the period the offer for sale is open.

(f) Offer for sale of units shall be open for a period of 23 days commencing from the 9th day of December 1991.

(g) The Trust shall not be obliged under any circumstances to offer for sale units after the offer period or if at its discretion the issue is closed earlier. Applications received after the close of business hours on 31st December, 1991 and subsequently at any of the authorised collection centres shall be deemed invalid and rejected.

V. INVESTMENT OBJECTIVE

(a) It shall be the endeavour of the Scheme to invest the capital after defraying all initial, preoperative and operational expenses in securities issued by companies listed on the recognised Stock Exchange in India. Investments over a period will be made mainly in equities convertible debentures of companies. The portfolio composition of investments will be with a view to achieving as far as practicable long term growth by reinvesting capital gains if any and paying out only the current and ordinary income after defraying expenses and making provisions.

(b) It shall be within the discretion of the Trust to decide about the composition of portfolio, subject to restrictions on investments and making income distribution having regard to the growth of the Scheme, the interest of investors and other relevant factors.

VI ALLOTMENT OF UNITS

(a) Allotment of units on applications shall be at the Trust's sole discretion and as nearly as practicable in he manner stated hereunder :—

(i) In the event of an undersubscription to the issue, allotment will be to the full extent.

(ii) The manner of and procedure for allotment shall be on such basis as the Trust may consider fair and equitable and the decision of the Trust in this behalf shall be final.

(b) Refund orders will be by bank instruments drawn in the name of the applicant in the case of a sole applicant or in the name of the first applicant in other cases.

VII APPLICATION AND TRANSFER FORMS SIGNED BY ATTORNEYS

If an application or transfer form is signed by a person holding a valid Power of Attorney, the original Power of Attorney or a certified copy duly notarised thereof should be submitted with the application or the transfer form, as the case may be, unless the Power of Attorney has already been registered in the books maintained by the Registrars.

VIII REGISTER OF UNITHOLDERS

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :—

(a) A register of unitholders shall be caused to be maintained by the Trust and these will be decided by the Trust. The register shall contain the following particulars :—

(i) The names and addresses of the unitholders

(ii) The distinctive number of unit certificate or certificates and the number of units held by every such holder; and

(iii) The date from which units are held in the name of the holder.

(b) In the event of death of a holder, any other person being entitled to the said units, upon recognition of the claim in such manner as the Trust may deem necessary such other person may be registered as a unitholder of units which shall always be in multiples of ten.

(c) Where a unit certificate is held in the name of two or three persons such persons shall be deemed to hold the units jointly on an either or survivor basis :—

(i) In either case it shall be deemed that the first of such persons is the holder of the units and transfers or other dealings, if any, shall be competent only by the first of such persons.

(ii) All payments to the first holder and a receipt thereof shall be a valid discharge to the Scheme.

(iii) The Scheme shall for all practical purposes correspond only with the first holder and all communications with the first holder shall be deemed to be valid discharge by the Scheme of its obligations.

(iv) In the case of death of a joint holder and survivor/(s) shall be the only person recognised by the Scheme as having any title to or interest in units represented by a certificate. Provided that the registration of units in the name of any person shall not affect or prejudice any right which any other person may have against a survivor/(s) in respect of the said units.

(d) Any charge in the name and address of a unitholder shall be notified to the registrars, the Registrars on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as may reasonably be required shall alter the register accordingly.

(e) Except when the register is closed as hereinafter provided, the register shall, during the business hours subject to such reasonable restrictions the Registrars may impose, but not less than two hours on each business day, shall be kept open for inspection by any unitholder.

(f) The register will be closed for such time and for such periods as the Trust may determine, so however, the registor shall not remain closed for more than 45 days in any one year. In the event of a closure of the register for a period or periods, notice shall be given by advertisements in not less than two leading English and one vernacular newspapers.

(g) The Registrars and the Scheme shall not receive notice of any Trust expressed or implied, constructive nor shall they be bound to enter any such notice in respect of any unit in the register except when so directed by a Court of Competent jurisdiction.

(h) In the event of death of a unitholder the Executors or Administrators or a holder of Succession Certificate issued under the Indian Succession Act, 1925, or a legal representative shall be the only persons who may be recognised by the Registrar as having any title to the units.

(i) A person becoming entitled to units in consequence of the death, insolvency or winding up of a sole holder or the survivor/(s) of joint holders, upon producing evidence to the satisfaction of the Registrar shall be registered as the holder of the units or permitted to transfer the units as the case may be.

(j) Notwithstanding anything contained in Clause (g) above if a unitholder pledges the certificate with a Scheduled Bank the interest of the pledgee shall be recorded in the register. If by enforcing the pledge the Scheduled Bank seeks to transfer the units and have it registered in its name, then the Registrar shall comply with the request and the register shall contain such particulars that the bank holds the certificate.

IX. TRANSFER OF UNITS SUBSEQUENT TO ISSUE

All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable after a period of six months from the date of allotment subject to the following terms :—

(a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause of the provisions of the scheme.

The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a unitholder under the scheme will be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) All transfers shall be made in such form the scheme may approve and shall be for a minimum of one hundred units and in multiples of hundred thereafter.

(d) Transfer instruments with the relative unit certificates accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(e) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Scheme shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(f) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars.

(g) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(h) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(i)3 Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(j) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the same or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of such a certificate or certificates.

(k) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

X NOMINATION BY UNITHOLDERS

(a) Unitholders may make substitute or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations.

(b) The Registrars subject to such directions and provisions of the Scheme may from time to time issue, shall accept a nomination in the forms prescribed and register the same. They may also subject to such directions permit the variation, modification or changes in such nominations and have them registered.

XI. PUBLICATIONS OF ACCOUNTS

The Trust shall, as soon as may be after the 30th June each year cause to be published in such manner as the Fund may decide acounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending out of that date. The Trust shall on a request in writing from a unitholder, furnish with a copy of the accounts so published.

XII. REDEMPTION OF UNITS

1. Neither the Trust nor the Mastershare Plus Scheme to be established shall be bound to redeem or repurchase the units for a period of 10 years.

2. Redemption or repurchase of the units shall be at the discretion of the Trust.

3. The units redeemed or repurchased by the Mastershare Plus Scheme shall be reissued at such price or prices, for such period or periods and on such terms and conditions as the Board decide in this behalf.

4. In no event the redemption price shall be fixed by the Mastershare Plus Scheme at a price less than that arrived by dividing the value of the assets pertaining to the Mastershare Plus Scheme reduced by the liability at the close of business on the day the price is determined by the number of units outstanding and deducting therefrom such sums as are adequate to cover brokerage, commission, taxes, stamp duties, and other charges in relation to realisation of investments adding thereto all other expenses and adjusting the price downwards by not more than 1% per unit. The price so determined shall be based on the material available with the Trust.

XIII. DISTRIBUTION OF INCOME TO UNITHOLDERS

(a) The Trust may or may not declare income distribution under the scheme depending upon the income received under the scheme and the expenses accrued thereunder. The income distributable if any, shall be paid as soon as may be after the Closing of Annual accounts on 30th of June each year.

(b) The Trust may decide to make such distribution of income as it considers necessary and transfer such sum or sums as it may deem fit out of the income not distributed to one or more reserve funds. The reserve funds which are not earmarked for application for any specific purpose shall be applied for or use only for the benefit of the unitholders.

(c) Income distribution to the unitholders shall be made as soon as may be, after the closing of the annual accounts of the Scheme as on 30th June each year.

(d) Such fo the unitholders whose name appear in the register of unitholders as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the Scheme shall be entitled to receive and retain the income so distributed.

(e) In case the unitholder has transferred the units prior to the declaration of income distribution and the transfer has not taken effect, the transferee shall not be entitled to the income distribution subsequently unless the transferee has lodged the transfer documents with the Registrars 30 days before the closure of the registers preceding the declaration of the income distribution.

(f) The income distributed shall be paid by the Master Plus Scheme by cheque or warrant drawn on its bankers with appropriate payment facilities.

(g) It shall be lawful for a unitholder to receive and any income distributed declared by the Scheme in respect of units of which he is a holder notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within 15 days of the date on which his income became due, lodged the certificate and all other documents relating to the transfer.

XIV. VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THE SCHEME :

(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Stock Exchange nearest to the principal place of business of the company whose securities are being valued and if such securities are listed on more than one Stock Exchange, then the Scheme may adopt the closing prices of the securities in the Stock Exchange nearest to the principal place of business of the company as being the fair value. If the securities have not been treated for more than six months prior to the date of valuation, then the Master Growth Scheme may value the security in the manner considered by it to be fair in consultation with its Auditors.

(b) Newly listed equity shares i.e. (the shares listed within the period of one year preceding the date of valuation) will be invariably valued at cost. A reduction or increase in the value of these equity shares will be based on the facts and circumstances which in the opinion of the Scheme appear to have a bearing or effect in such upward or downward valuation.

(c) Money market instruments and other fixed income bearing instruments including debentures which are not convertible will be valued on the basis of current yield and maturity value of comparable instruments.

(d) To the value determined as above shall be added the interest accrued in the case of fixed income securities and debentures and the dividend declared but not received in respect of equity shares.

(e) All other assets not capable of being valued as aforesaid shall be valued at their book value.

XV. PUBLICATION OF THE NET ASSET VALUE

(a) The Net Asset Value of the Master Growth Scheme shall be calculated at Bombay in accordance with the rovisions of Clause XIV hereinafter given at the close of business on each Thursday (or the previous working day if it is a holiday) after deducting from the said aggregate value the liabilities incurred for the said Master Grwoth Scheme and other expences on a proportionate basis which in the opinion of the Master Growth Scheme is sufficient to cover the stamp duties taxes and other expenses payable on a deemed realisation of the investment and shall be published in the leading daily newspapers in India. Intimation will also be sent simultaneously to all the Stock Exchanges in India of the said value in a manner most suitable. Valuation so published shall be valid till the next publication of value.

(b) In the event of unforeseen circumstances, if the valuation is not so published for a given week or for one or more such weeks, the Trust shall not be deemed to have violated any of the terms of offer of units by it.

(c) Trading of units over Stock Exchange shall always be deemed between intending buyers and sellers for genuine investment purposes and the Scheme shall have not control over such tradings.

XVI. TRADING OF UNITS :

(a) The units will be listed in Stock Exchanges at such place/s as may be decided by the Trust. The Trust will announce the net asset value determined on Thursday on the previous working day if it is a holiday and intimate the value to all the Stock Exchanges for the purpose of being quoted.

(b) A unitholder desirous of liquidating his holdings may trade the units through any of the Stock Exchanges.

(c) The Trust will not either dericetly or in any manner indicate the price or prices at which the units could be bought or sold through the market. However, the last prices at which units were brought or sold at the Stock Exchanges in a trading will be published in leading daily newspapers.

(d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the relative unit certificates to the Registrars of the Scheme giving effect to the transfer if found in order.

(e) No application for transfer will be accepted by any offices of the Trust and the Trust will not deal with the unitholders of the Scheme for any purpose.

(f) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unitholder or a prospective unitholder. However, for the purpose of determining the stamp duty to any payable on transfer of units the average of the high and low prices that ruled on the date prior to the date of transfer shall be the basis for the charge.

XVII. RESTRICTION ON INVESTMENT :

(a) Investment by the Trust of its investible funds under the Scheme in the securities issued by any one company shall not exceed 10% of the total funds or 15% of the securities issued and outstanding of such company whichever is less.

(b) Investment by the Trust of its investible funds under the Scheme in the securities of any new company shall not exceed 10% of the securities issued by such company and the aggregate of all such investments shall not exceed 30% of the investible funds.

Explanation : A new company means a company whose shares have been listed on any Stock Exchange first within one year prior to investment in the shares by the fund.

(c) The Trust may for operational convenience or to seek changes in opportunities keep invested at any time not exceeding 20% of the total funds in any short term money market instrument, convertible or non-convertible debentures, bank deposits, bills rediscounted or similar other avenues.

Provided that till the Trust fully employs the funds of the scheme in securities, it may keep the funds not so employed invested in such securities as may be considered expedient including those referred to in Clause (c) above.

(d) The restrictions on investment prescribed shall be applied with reference to circumstances at the time the investments are made and shall not be deemed to have been exceeded, notwithstanding that, by reason of fluctuation in the market price or investments, or by reason of issue of bonus shares or right shares by the company in whose securities investments have been made, the limit is in fact exceeded.

XVIII. SCHEME TO BE BINDING ON UNITHOLDERS

The terms of this Scheme including any amendments there of made from time to time (provided such amendments do not vary the basic character and the purpose of this Scheme seeks to achieve) shall be binding on each unitholder and any person or persons claiming through or under him as if he/they had expressly agreed that they should be binding.

XIX. COPY OF SCHEME TO BE MADE AVAILABLE :

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made aavilable for inspection at the offices of the Registrars or of the Scheme (when established) at all times during its business hours and may be supplied upon payment of Rs. 5/- to a unitholder.

XX. ADDITIONS AND AMENDMENTS TO SCHEME :

The Board may subject to such directions the Board of the Trust gives from time to time add to or otherwise amend or alter this Scheme and any amendment or alteration thereof will be notified in the Official Gazette.

MASTERSHARE PLUS UNIT SCHEME—1991

UNIT TRUST OF INDIA

13, SIR VITHALDAS THACKERSEY MARG
(NEW MARINE LINES)
BOMBAY-400 020

THIS IS TO CERTIFY that the person(s) named in this Certificate is/are the Registered Holder(s) of the within-mentioned Master-shares bearing the distinctive number(s) herein specified in MASTERSHARE PLUS UNIT SCHEME-1991 subject to the provisions of the MASTERSHARE PLUS UNIT SCHEME-1991. The amount endorsed hereon has been paid up on each such Mastershares.

MASTER PLUS EACH ON RUPEES 10/-

AMOUNT PAID UP PER MASTERSHARE RUPEES 10/-

Certificate No.

Name(s) of Holder

(1) _____

(2) _____

(3) _____

No. of share held _____

Distinctive No. (s) _____

Given on this day of 1992

MASTERSHARE PLUS UNIT SCHEME-1991

CHAIRMAN :

TRUSTEE:

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt. dated the 28th January 1992.

No. Wakf/45/Gen./Pub/Gazette/488/92-In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1954 which is exerciseable by me under delegation of powers by the Administrator, Punjab Wakf Board under Section 22 of the Wakf Act, 1954, the following properties are hereby declared as Sunni Wakf.

S. No.	Name of Wakf	District/Tehsil	Village	Khasra No.	Area	Value	Nature and Object of Wakf	How the Wakf is administered.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Graveyard	Panipat / Panipat	Asan Kalan	166 158 160 162 162/1 Total	K—M 8—10 0—15 0—15 1—05 2—14 13—19	3,50,000.00	Religious	Under the management of Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.	Sunni Wakf
2.	Mosque	Gurgaon / FP Jhirka	Nagina	77/18	0—05	50,000.00	Do.	Do.	Do.
3.	Graveyard	Do.	Do.	170	0—18	20,000.00	Do.	Do.	Do.
4.	Madrasa Islamia	Do.	Do.	265	10—17	3,00,000.00	Do.	Do.	Do.
5.	Graveyard	Gurgaon / Gurgaon	Hidayatpur Cantt. (Gurgaon)	422 Min	B—B 0—05	20,000.00	Do.	Do.	(do) Ghair Mumkin Qaburustan as shown in the Jamabandi for the year 1963. The property has been leased out to Shri Shamsher Singh Malik Rs. 8/-PM w.e.f.1-3-68.
6.	Mosque	Kaithal / Kalayat	Kalayat	288/4	K—M 9—14	1,25,000.00	Do.	Do.	Do.
7.	Graveyard	Do.	Do.	7 8/1	2—19 3—04 6—03	75,000.00	Do.	Do.	Do.
8.	Graveyard	Do.	Do.	888 889	0—08 23—14 24—02	3,00,000.00	Do.	Do.	Do.
9.	Mosque	Rohtak / Rohtak	Sanpla HB 35	3133 Masjid within abadi	B—B—B 0—2—091	1,50,000.00	Do.	Do.	Do.

				3134	Shop of Masjid	0—0—08 0—2—17				
10. Graveyard . .	Do.	Do.	1237 1273			0—7—0 0—20—0 0—9—0	1,00,000.00	Do.	Do.	Do.
11. Graveyard . .	Sangrur Sunam	Sunam	623/1			K—M 9—16	8,00,000.00	Do.	Do.	Do.
12. Takia . . .	Ludhiana Ludhiana	Saidan Ludhiana	Within abadi North—Road South—Hosiery Building East—Inayat Ganj Road West—Open space			2628 Sq. Yds	26,00,000.00	Do.	Do.	Do.
13. Khanqah . .	Do.	Matewara HB 45	75 1			8—00	1,20,000.00	Do.	Do.	Do.
14. Graveyard . .	Kapurthala Sultanpur	Hussainpur Dulowal HB 64	60			12—13	1,50,000.00	Do.	Do.	Do.
15. Graveyard . .	Kapurthala Sultanpur	Jarjpur Meripur HB 43	123			K—M 4—02	30,000.00	Religious	Under the management of Wakf Board, Ambala Cantt.	Punjab Suni Wakf
16. Graveyard . .	Do.	Do.	160			10—12	80,000.00	Do.	Do.	Do.
17. Graveyard . .	Amritsar Ajnala	Dayal Bharang HB 254	49			18—01	4,00,000.00			
18. Mosque . . .	Faridkot Muktasar	Gonyana	N—House of Shri Asa Singh S—Street E—Way W—House of Shri Chanan Singh s/o Shri Sohan Singh				60,000.00	Do.	Do.	Do.
19. Graveyard . .	Do.	Sotha HB 35	167			27—05	4,50,000.00	Do.	Do.	Do.
20. Graveyard . .	Ferozpur Ferozpur	Lopo HB 157	139			20—07	10,00,000.00	Do.	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Khanqah Baba Farid Gudar Shah	Gurdaspur / Batala	Kastiwal HB 264	67	54—00				
				15/13R	3—00				
				14	8—00				
				4/2 Min	3—00				
				5	8—00				
				6/1	2—05				
				6/12	0—11				
				7/1	0—09				
				7/2	7—05				
				6/1	5—00				
				23	8—00				
				24	7—12				
				16/1	3—15				
				16/2	3—08				
				25	7—12				
				4/1	3—17				
				27R/1	8—00				
				2	8—00				
				3	8—00				
				4	8—00				
				10/1	2—00				
				7/1	0—18				
				28R/5	4—08				
				14R/6/2	6—00				
				13	8—00				
				16	8—00				
				15	8—00				
				1	4—02				
				2/1	4—04				
				23	8—00				
				17	8—00				
				18	8—00				
				19	8—00				
				20	4—12				
				21	7—14				
				22	8—00				
				24	8—00				
				7	8—00				
				8	8—00				
				14	8—00				
				16R/11/1	5—12				
				11/1	1—04				
				25R/19/1	3—12				
				11	8—00				
				20/1	3—11				
				20/2	4—09				
				1	8—00				
				26 R/4	7—12				
				5 Min	3—16				
				6 Min	3—16				
				7 Min	3—04				
				15	7—12				
				11R/23	7—07				
				24	8—00				
				18	8—00				
				25	8—00				
				13R/25	0—13				
					387—00				

22. Khanqah Baba Farid Gadi, Shah	Gurdaspur / Batala	Gujerpura HB 265	37R/24	3—06	15,90,000.00	Religious	Under the management of Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.	Sunni Wakf
			25	8—00				
			15	8—00				
			16	8—00				
			17	7—05				
			18	0—05				
			13	3—10				
			14	8—00				
			40R/11	6—19				
			20	3—00				
			12	8—00				
			18	8—00				
			19	8—00				
			23	7—02				
			24	0—04				
			13	8—00				
			1	8—00				
			21	0—03				
			22	7—01				
			14	6—10				
			2/1	5—11				
			17	3—02				
			41R/15	0—03				
			4	0—04				
			5	7—01				
			6	3—02				
			46R/22	8—00				
			25	8—00				
			15	7—15				
			17	8—00				
			24	8—00				
			14	8—00				
			16	8—00				
			23	8—00				
			3	7—16				
			8	8—00				
			13	8—00				
			21	8—00				
			18	8—00				
			4	7—06				
			5	0—06				
			6	3—10				
			7	8—00				
			47R/11	0—06				
			20	3—14				
			21	7—02				
			49R/1	8—00				
			2	8—00				
			12	8—00				
			19	7—10				
			9	8—00				
			10	8—00				
			11	8—00				
			20	8—00				
			22	7—03				
			8	8—00				
			21/1	7—05				
			14	8—00				
			18 Min	3—12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6	8—00				
				7	8—00				
				17	8—00				
				24	7—16				
				13	8—00				
				23	2—08				
				4	8—00				
				5	8—00				
				16	3—10				
				3	8—00				
				25	0—11				
				50R/15/2	2—12				
				16	8—00				
				17	7—18				
				6	4—04				
				15	6—16				
				23	8—00				
				12	7—10				
				21	7—04				
				22	8—00				
				9	1—16				
				8	3—13				
				13 Min	6—00				
				24	3—14				
				29R/2	8—00				
				8	0—02				
				9	5—05				
				12	0—02				
				1	7—04				
				10	7—04				
				11	2—12				
				3	4—17				
				4	0—01				
				30R/5/2	4—00				
				6	8—00				
				15	5—18				
				38R/20	8—00				
				21	8—00				
				12/1	5—00				
				19	8—00				
				10/2	4—00				
				11	8—00				
				48R/11	0—04				
				1	6—12				
				10/Min	1—00				
				54R/1/3	0—08				

				3/2	7—13			
				2/1	3—14			
				4	5—00			
				7/1	1—00			
				7/3	0—01			
				8/1	1—04			
				8/2	0—19			
					670—19	28,75,000.00	Religious	Under the management of Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.	Sunni Wakf
					K—M				
23. Masjid . . .	Gurdaspur	Dayalgarh		8/5	0—07	1,75,000.00	Religious	Under the management of Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.	Sunni Wakf
	Batala	HB 227		6	6—00				
				12/1/1	0—02				
				1/2	1—18				
				2/1	3—14				
				9/2	4—13				
				10	8—00				
					24—14				
24. Graveyard . .	Do.	Batala		1773/2	7—05	3,75,000.00	Religous	Do.	Do.
		Gharbi		1773/1	6—00				
		HB 211		1941	3—12				
				96/26	7—18				
				937/2	2—05				
				1960/4	2—00				
				79/27	8—03				
				80/6/2	1—08				
				82/29	4—18				
				76/29	0—04				
				1909	4—15				
				1910/2	0—02				
				81/31	5—16				
25. Idgah . . .	Do.	Do.		41	6—01				
26. Masjid . . .	Do.	Do.		7/17	2—06				
				6/16/2	1—19				
				7/18/1/2	0—17				
				23/2	2—04				
				7/11/1/3	0—14				
				7/24	9—14				
				63/31	0—08				
				23/28	0—17				
					79—06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Masjid . .	Do.	Batala Chowk Chokri Bazar	MC Old B-I/105 New B-XL-II 105	175 Sq. Yds.	60,000.00	Religious	Under management of Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.	Suoni wakf
			Shop Do.	Do.	10 Sq. Yds	25,000.00	Do.	Do.	Do.
			Shop Do.	Do.	6 Sq. Yds	12,000.00	Do.	Do.	Do.

The above items Graveyard, Mosque, Madrasa, Takia, Khanqah, Idgah & Shops are declared as Sunni Wakfs shown in the Jamabandis.

F. O. HASHMI,
Secretary,
Punjab Wakf Board,
Ambala Cantt.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992